विजय मत

राष्ट्र को समर्पित

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

www.vijaymat.com | भोपाल, शुक्रवार, 13 फरवरी 2026 | वर्ष- 11 | अंक- 66 | पेज- 08 | मूल्य- 5 रुपए

ज्ञानामृत

घर मे यदि दीपक न जले तो वह दरिद्रता का चिन्ह है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हृदय मे ज्ञान दीपक जला कर उस को देखो।

▶▶ श्री रामकृष्ण परमहम

न्यूज इन शॉर्ट

रिटेल महंगाई 8 महीने के उच्चतम स्तर पर, जनवरी में 2.75% पहुंची

नई दिल्ली, एजेंसी। खुदरा महंगाई दर में जनवरी महीने में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित रिटेल महंगाई बढ़कर 2.75 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो पिछले आठ महीनों का उच्चतम स्तर है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में महंगाई दर 0.25 प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर थी। आंकड़ों के अनुसार, खाद्य पदार्थों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह रही। सब्जियों, दालों और कुछ आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दाम में उछाल का सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ा है। हालांकि, महंगाई अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित लक्ष्य दायरे के भीतर बनी हुई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों का असर घरेलू बाजार पर दिखाई दे रहा है।

चांद पर फैक्ट्री लगाने की तैयारी में इलॉन मस्क की एआई कंपनी

वॉशिंगटन, एजेंसी। दुनिया के चर्चित उद्योगपति एलन मस्क ने एक महत्वाकांक्षी योजना का संकेत दिया है। उनकी एआई कंपनी चांद पर फैक्ट्री स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है, जिसका उद्देश्य सूर्य की ऊर्जा को सीधे अंतरिक्ष में कैप्चर कर पृथ्वी तक पहुंचाना है। मस्क के अनुसार, यदि यह परियोजना सफल होती है तो इससे ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। चांद की सतह पर स्थापित सोलर सिस्टम पृथ्वी की तुलना में अधिक स्थिर और निर्बाध रूप से सूर्य की किरणों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहां मौसम या बादलों जैसी बाधाएं नहीं होतीं। मस्क ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष में इस तरह के प्रयोग भविष्य में मानव सभ्यता के लिए नए द्वार खोल सकते हैं। उनका मानना है कि उन्नत एआई और अंतरिक्ष तकनीक के मेल से इंसानों को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिल सकती है।

गाजा में इजराइल द्वारा प्रतिबंधित वैक्यूम बम के इस्तेमाल का दावा

वाशिंगटन, एजेंसी। गाजा पट्टी में जारी संघर्ष के बीच इजराइल पर प्रतिबंधित वैक्यूम बम (थर्मोबैरिक हथियार) इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय सूत्रों का दावा है कि हालिया हमलों में ऐसे बमों का प्रयोग हुआ, जिनसे अत्यधिक तापमान और दबाव पैदा हुआ। रिपोर्टों के अनुसार, इन विस्फोटों के दौरान तापमान लगभग 3,500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे व्यापक तबाही हुई। आरोप है कि इन हथियारों के प्रभाव से इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। हालांकि, इजराइली पक्ष ने इन आरोपों पर आधिकारिक रूप से विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्यूम बम पारंपरिक विस्फोटकों से अलग होते हैं और विस्फोट के साथ तीव्र दाब तरंग उत्पन्न करते हैं।

चांदी में बड़ी गिरावट, 5,835 रुपए टूटी; सोना भी 1,175 रुपए फिसला

नई दिल्ली, एजेंसी। सर्राफा बाजार में गुरुवार को कीमती धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत 5,835 रुपए प्रति किलो घटकर 2.61 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई। लगातार उतार-चढ़ाव के बीच यह गिरावट निवेशकों के लिए अहम मानी जा रही है। वहीं सोने के दाम में भी कमजोरी देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 1,175 रुपए सस्ता होकर लगभग 1.56 लाख रुपए पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में नरमी और डॉलर की मजबूती का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक आर्थिक संकेतकों, ब्याज दरों और डॉलर इंडेक्स में बदलाव का सीधा प्रभाव सोना-चांदी की कीमतों पर पड़ता है। इसके अलावा, निवेशकों की मुनाफावसूली भी गिरावट का एक कारण मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शोधार्थी समागम 2026 को किया संबोधित

शोध उच्च कोटि का होना चाहिए जो हमारी सोच को नई दिशा दें : मोहन

विजय मत, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शोध मात्र अकादमिक गतिविधि नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की दिशा बदलने वाली शक्ति है। शोध इतना उच्च कोटि का होना चाहिए जो हमारी सोच को नई दृष्टि और नई दिशा प्रदान करे। उन्होंने शोधार्थियों से आह्वान किया कि वे देश के विकास के लिए अपनी जिज्ञासा और रुचि के क्षेत्रों में निर्भीक होकर आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री गुरुवार को मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के विज्ञान भवन में श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय शोधार्थी समागम (नेशनल रिसर्चर्स मीट) 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसे ही शोध विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धतियों का जनक है। जब मानवीय प्रज्ञा में वैज्ञानिक ज्ञान का समावेश होता है, तब वह 'प्रज्ञान' का रूप ले लेता है।

विज्ञान के विकास में ही देश का समग्र विकास निहित है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विज्ञान के विकास में ही देश का समग्र विकास निहित है और मध्यप्रदेश को शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने शोधार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे परंपरागत धारणाओं तक सीमित न रहकर आधुनिक, परिष्कृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले शोध प्रस्तुत करें।

भारतीय दृष्टि से हो शोध

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के ज्ञान पर पश्चिम का प्रभाव रहा है, किंतु भारत की परंपरा समाज आधारित शोध की रही है। शोध राष्ट्र कल्याण केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान राष्ट्रीय शोधार्थी समागम के माध्यम से देश के शोधार्थियों को नई दिशा प्रदान कर रहा है।

वेबसाइट व पुस्तकों का विमोचन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महाकाल- द मास्टर ऑफ टाइम वेबसाइट का शुभारंभ, महाकाल ब्रोशर सहित 41वें मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन एवं विज्ञान उत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही अनुसंधानपरक लेखन पर आधारित सात पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया।

ऐसी कार्यशालाएं अभियंताओं की स्किल्स को रिफ्रेश करती हैं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोक निर्माण विभाग के तकनीकी अधिकारियों, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अभियंताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैचारिक प्रतिबद्धता और कार्यशैली में जड़ता से बचने और बदलती तकनीकों के अनुरूप स्वयं को अद्यतन रखने के लिए कौशल संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। ऐसी कार्यशालाएं अभियंताओं की स्किल्स को रिफ्रेश करती हैं और उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में दीर्घकालिक दृष्टि, नवाचार और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

विचारकों ने रखे अपने मत

पूज्य आचार्य मिथलेशनन्दिनीशरण महाराज ने कहा कि शोध हमें बोध तक ले जाए, तभी उसका महत्व है। केवल डाटा आधारित अध्ययन पर्याप्त नहीं, बल्कि चिंतन आधारित ज्ञान आवश्यक है। वरिष्ठ लेखक एवं चिंतक सुरेश सोनी ने कहा कि भारतीय समग्रता को ध्यान में रखकर शोध कार्य होना चाहिए। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रो. मधुकर एस. पड़वी ने स्वदेशी दृष्टि अपनाने और सहयोगात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया।

'घूसखोर पंडित' शीर्षक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, रिलीज पर लगाई रोक

नाम बदले बिना नहीं होगी फिल्म रिलीज, केंद्र और सीबीएफसी को नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'घूसखोर पंडित' के शीर्षक पर कड़ी आपत्ति जताते हुए फिल्ममेकर नीरज पांडे को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी फिल्म का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे समाज के किसी वर्ग को बदनाम किया जाए। मनोज बाजपेयी अभिनीत यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयान की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि ऐसे शीर्षक नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक फिल्म निर्माता बदला हुआ नाम प्रस्तुत नहीं करते, तब तक फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी। साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

बदला हुआ नाम बताना अनिवार्य

पीठ ने फिल्म निर्माताओं को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि फिल्म किसी भी समाज या वर्ग को नीचा नहीं दिखाती। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की गई है।

याचिका में क्या कहा गया

फिल्म के खिलाफ दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि शीर्षक जाति और धर्म आधारित स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देता है तथा सांप्रदायिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यह याचिका भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संगठन सचिव अतुल मिश्रा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। फिल्म के नाम को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हुए।

लोकसभा: भाजपा सांसद ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिस दिया

राहुल पर विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाएगी सरकार, भाषण के अंश हटाने की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया भाषण को लेकर उठा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने से फिलहाल इंकार कर दिया है, हालांकि, बीजेपी उनके (राहुल) भाषण से आपत्तिजनक हिस्से हटाने को लेकर अब भी अड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने आरोपों को लेकर सबूत पेश नहीं किए हैं।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफटाइम बैन लगाने की मांग की है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदीजी ने छाती 56 इंच की नपवाई थी। उनके खिलाफ भी प्रस्ताव आना चाहिए। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल के बजट चर्चा के दौरान कहे गए कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का औपचारिक नोटिस दिया है। इससे पहले, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैंबर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दीं।

पीएम मोदी आज नए कार्यालय में शिफ्ट होंगे, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 व 2 का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को नए निर्मित कार्यालय परिसर में कार्यभार संभालेंगे। इस अवसर पर 'सेवा तीर्थ' के साथ कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। यह बदलाव केंद्र सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक, केंद्रीकृत और अधिक सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए कार्यालय परिसर के शुरू होने के साथ ही ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में स्थित कई मंत्रालयों को चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित किया जाएगा।

डीएसी ने ₹3.25 लाख करोड़ के रक्षा महानुबंध को दी मंजूरी

आसमान से समंदर तक बढ़ेगी ताकत 114 राफेल और 6 पी-8आई को मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी

देश की सुरक्षा संरचना को अभूतपूर्व मजबूती देते हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 114 आधुनिक लड़ाकू विमानों और 6 पी-8आई समुद्री निगरानी विमानों की खरीद पर सहमति बनी। यह फैसला भारतीय वायु और समुद्री शक्ति के विस्तार की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है। स्वीकृत प्रस्ताव के तहत बड़ी संख्या में विमानों का निर्माण भारत में ही किए जाने की रूपरेखा है, जिससे 'मेक इन इंडिया' पहल को नई गति मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, यह सौदा वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन स्तर को संतुलित करने और समुद्री सीमाओं पर निगरानी क्षमता को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। वर्तमान में भारतीय वायु सेना के पास स्वीकृत संख्या से कम स्क्वाड्रन हैं, जबकि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर अपनी निगरानी क्षमता का विस्तार कर रही है।

बागेश्वर धाम के प्रमुख पं. धीरेंद्र शास्त्री का कड़ा संदेश

सिर्फ 'सीताराम' भर कह देने से धर्म की रक्षा नहीं होगी, अब माला के साथ भाला भी रखना होगा

विजय मत, ब्यूरो छतरपुर। बागेश्वर धाम के प्रमुख और प्रसिद्ध धर्म प्रचारक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुवार को एक बार फिर चर्चा में आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आज के समय में केवल सीताराम-सीताराम का जाप भर करने या माला हाथ में लेने से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, बल्कि उसके साथ भाला यानी आत्म-रक्षा के साधनों का भी होना आवश्यक है। यह टिप्पणी उन्होंने धर्म संरक्षण और समाज में बढ़ते तनाव के संदर्भ में कही। शास्त्री ने अपने प्रवचनों में हिंदुओं से आग्रह किया कि वे आस्था तो रखें, लेकिन स्वयं की रक्षा की तैयारी भी रखें।

उनका यह बयान सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे यह स्पष्ट करते दिख रहे हैं कि हमारे पास माला भी है और भाला भी संकेत देते हुए आत्म-संरक्षण की आवश्यकता पर जोर। धर्म और संस्कृति की एकता पर बल देते हुए शास्त्री ने यह भी कहा कि केवल धार्मिक शब्दों के उच्चारण से सामाजिक चुनौतियों का समाधान नहीं होगा, बल्कि जागरूकता, एकता और आत्म-रक्षा की भावना भी जरूरी है। शास्त्री का कहना है कि धर्म की रक्षा सिर्फ भक्ति से नहीं, बल्कि एकजुटता, समझ और साहस से होती है।

विदेश मंत्रालय ने संशोधित अमेरिकी दस्तावेज पर दी सफाई

दोनों देशों द्वारा जारी बयान ही भारत-अमेरिका डील का आधार, प्रक्रिया तय सहमति के अनुसार होगी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी संशोधित इंडिया-यूएस ट्रेड फ्रेमवर्क फैक्टशीट दोनों देशों के बीच बनी सहमति के अनुरूप है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 7 फरवरी 2026 को जारी संयुक्त वक्तव्य ही इस पूरी प्रक्रिया का आधार है और अमेरिकी दस्तावेज उसी साझा समझ को प्रतिबिंबित करता है। दोनों देश अब तय ढांचे को लागू करने और समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश चुनाव पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पहले जनादेश स्पष्ट होने का इंतजार किया जाना चाहिए। भारत का रुख स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव के समर्थन में रहा है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर आएंगे। वे दिल्ली में होने वाले एआई समिट में भाग लेंगे और 21 फरवरी को उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता होगी। व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग पर विशेष जोर रहेगा। अमेरिका के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने के प्रस्ताव पर मंत्रालय ने कहा कि भारत इसे गंभीरता से परख रहा है।

मुरैना हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचला, तीन की मौत

आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम

विजय मत, ब्यूरो मुरैना

मुरैना में नेशनल हाईवे पर गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में सास, बहू और नातिन की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और आरोपित चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों महिलाएं सड़क पर गिर पड़ीं और ट्रक उन्हें कुचलते हुए निकल गया। मौके पर ही सावित्री देवी (सास), रीना देवी (बहू) और मासूम आराध्या (नातिन) की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर, परिजनों और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।

विजय मत एंकर | 9 से 17 वर्ष के बच्चे रोजाना 3 घंटे से अधिक इंटरनेट पर सक्रिय, अभिभावकों ने जताई चिंता

लोकल सर्किल्स सर्वे... हर दूसरा बच्चा ऑनलाइन बुलिंग का शिकार

नई दिल्ली, एजेंसी

डिजिटल युग में बच्चों की ऑनलाइन मौजूदगी अब गंभीर सामाजिक चुनौती का रूप लेती जा रही है। एक ताजा सर्वे में सामने आया है कि देश में हर दूसरा बच्चा ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हो चुका है। यह खुलासा लोकलसर्किल्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में हुआ है, जिसमें 9 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की इंटरनेट उपयोग की आदतों और उससे जुड़े जोखिमों का विश्लेषण किया गया। सर्वे के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत अभिभावकों ने स्वीकार किया कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म या मैसेजिंग एप्स के माध्यम से अपमानजनक टिप्पणियों, ट्रोलिंग, धमकी या मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। कई अभिभावकों ने बताया कि ऐसी घटनाओं के बाद बच्चों के व्यवहार में बदलाव, चिड़चिड़ापन और आत्मविश्वास में कमी देखी गई।

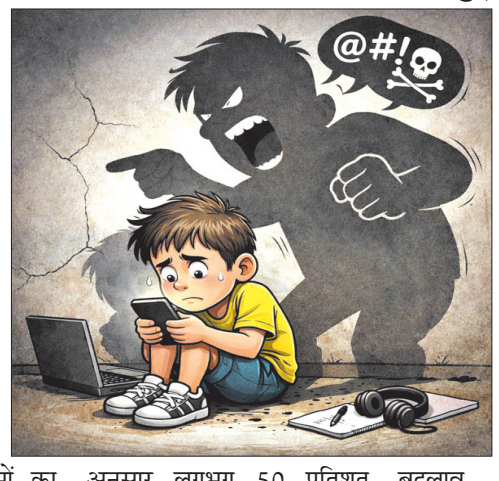

स्क्रीन टाइम भी चिंता का कारण

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 9 से 17 वर्ष के बच्चे प्रतिदिन औसतन तीन घंटे से अधिक समय ऑनलाइन बिताते हैं। किशोर आयु वर्ग में यह समय और अधिक पाया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार स्क्रीन टाइम का असर बच्चों की नींद, पढ़ाई और सामाजिक व्यवहार पर पड़ रहा है।

मानसिक स्वास्थ्य पर असर

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऑनलाइन बुलिंग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। कई बच्चे डर या शर्म के कारण अपने माता-पिता को इस बारे में नहीं बताते। ऐसे में समय रहते पहचान और संवाद बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि अभिभावक बच्चों के डिजिटल व्यवहार पर संतुलित निगरानी रखें, नियमित बातचीत करें और आवश्यकता पड़ने पर पेशेवर काउंसलिंग की मदद लें।

जागरूकता की जरूरत

रिपोर्ट में स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को भी डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक का सही उपयोग बच्चों के विकास में सहायक हो सकता है, लेकिन बिना मार्गदर्शन के यह जोखिम भी पैदा कर सकता है।

प्रधान संपादक- विजय शुक्ला। कार्यालयः भोपाल ■ शहडोल ■ रायपुर ■ इंदौर ■ जबलपुर ■ होशंगाबाद ■ विदिशा ■ सीहोर ■ बैतूल ■ छिंदवाड़ा ■ ग्वालियर ■ ब्यौहारी ■ अनूपपुर ■ उमरिया ■ सीधी ■ सिंगरौली ■ रीवा ■ सतना ■ मैहर ■ खरगोन ■ बालाघाट ■ सिवनी ■ कटनी ■ सागर ■ मुलताई ■ मुरैना ■ टीकमगढ़

न्यूज इन शॉर्ट

अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

सीधी। जिले के ग्राम बुढ़गौना में अल्ट्राटेक सीमेंट के सीएसआर विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा।
यह शिविर इकाई प्रमुख बीपी सम्राट, मानव संसाधन विभाग प्रमुख अभिषेक शर्मा एवं प्रशासनिक विभाग प्रमुख दिनेश शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सीएसआर टीम की सक्रिय भूमिका रही। रेड क्रॉस सोसायटी एवं संजय गांधी अस्पताल रीवा के चिकित्सकों द्वारा कुल 121 मरीजों की जांच की गई। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां एवं आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया। शिविर में ग्राम सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने इस जनकल्याणकारी पहल की सराहना करते हुए इसे स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। यह आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अमरपुर में श्रीमद्भागवत का हुआ आयोजन

सीधी। जिले के ग्राम पंचायत अमरपुर चुरहट में लालमणि त्रिपाठी के निवास पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किया गया। नंदनंदन पाण्डेय महराज के आशीर्वाद से उनके पुत्र प्रशिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं युवा कथावाचक राधाकांत पाण्डेय श्रीराधा कृपा संस्थान रीवा के द्वारा श्रीमद्भागवत कथा का रसपान भक्तों को कराया गया। सप्तदिवसीय कथा के यजमान लालमणि त्रिपाठी एवं उनके परिवार जनों ने भावविभोर होकर कथा का रसास्वादन किया। कथा के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से कथा श्रवण के लिए पहुंचते थे।
कथावाचक राधाकांत पाण्डेय के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीला, गोवर्धन पूजा, भक्ति मार्ग तथा मानव जीवन में धर्म, कर्म और सेवा के महत्व पर विस्तार से प्रवचन दिए। प्रवचनों को सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे और पूरे गांव का वातावरण भक्तिमय बना रहा। प्रतिदिन कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमडने लगती थी। भजन-कीर्तन और जयकारों से गांव गूंजता रहा। सातवें दिन हवन-पूजन, वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूर्णाहुति के साथ श्रीमद्भागवत कथा का विधिवत समापन किया गया। इसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। इस कार्य में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। श्रीमद्भागवत कथा के समापन आवसर पर कथा व्यास राधाकृष्ण पाण्डेय के द्वारा कृष्ण सुदामा चरित्र का अद्भुत वर्णन किया गया। कथाव्यास ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए यह भगवान श्री कृष्ण सुदामाजी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुदामा अपनी पद्दी के आग्रह पर अपने मित्र से सखा सुदामा मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे।

झूला पुल तालाब में तड़पकर मर रही मछलियां

जहरीले अपशिष्ट और लापरवाही के बीच दम तोड़ता पारिस्थितिकी तंत्र, विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल , प्रदूषण से कराहता शहर का हृदय स्थल

विजय मत, शहडोल

शहर की पहचान और हृदय स्थल माने जाने वाला झूला पुल तालाब इन दिनों गहरे पर्यावरणीय संकट से गुजर रहा है। हाल ही में तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां मृत पाई गईं थी। पानी की सतह पर तैरती मछलियों और किनारों पर पड़े शवों ने पूरे शहर को झकझोर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मछलियां काफी देर तक तड़पती रहीं, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।

जहरीले पानी में घुट रही मछलियों की सांसें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तालाब का पानी पिछले कुछ समय से बदरंग और दुर्गंधयुक्त हो गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से गिर चुका है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो मछलियां सांस नहीं ले पातीं और दम घुटने से उनकी मौत हो रही है। यह स्थिति पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे का संकेत है। एक रिटायर वैज्ञानिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पानी में गंदगी ज्यादा हो जाती है तो पानी में बैक्ट्रिया पनपने लगते है, जिससे ज्यादा आक्सीजन बैक्ट्रिया द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और जल में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं को आक्सीजन नहीं मिल पाता है जिसके वजह से पानी में मछली मर रही है।

मेडिकल वेस्ट बना बड़ा खतरा

स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने आरोप लगाया है कि आसपास संचालित कुछ निजी अस्पतालों का मेडिकल अपशिष्ट नालियों के माध्यम से सीधे तालाब में प्रवाहित हो रहा है। यदि यह आरोप सही है तो यह न केवल पर्यावरणीय अपराध है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। मेडिकल वेस्ट में मौजूद रसायन और संक्रमणकारी तत्व पानी को विषैला बना सकते हैं।

सफाई और निगरानी व्यवस्था पर सवाल

नगरपालिका की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। तालाब की अंतिम बार व्यापक सफाई कब हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। नियमित जल परीक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था नजर नहीं आ रही। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐतिहासिक और सार्वजनिक महत्व के इस तालाब के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक योजना और सख्त निगरानी तंत्र की आवश्यकता है।

चौपाटी और दुकानों की गंदगी से बढ़ा प्रदूषण

तालाब के किनारे संचालित खाने-पीने की दुकानों और चौपाटी क्षेत्र से निकलने वाला प्लास्टिक कचरा, बचा हुआ भोजन और अन्य अपशिष्ट भी बिना रोक-टोक के तालाब में डाला जा रहा है। प्लास्टिक और जैविक कचरा पानी की गुणवत्ता को तेजी से प्रभावित करता है, जिससे सड़न और दुर्गंध बढ़ती है। लंबे समय से कचरा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था न होने के कारण हालात बिगड़ते चले गए।

इनका कहना है।

हमने रिपोर्ट भेजी थी जिसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से मछलियों को मरना पाया गया है। पाइज़न की रिपोर्ट अभी आना बाकी है।
मोतीलाल सिंह सफाई प्रभारी नपा शहडोल

शहडोल संभाग की कनेक्टिविटी चरमराई-वादों के बीच फंसा विकास

विजय मत, शहडोल

मंचों से किए गए बड़े-बड़े वादों और सरकारी फाइलों में दर्ज योजनाओं के बीच शहडोल संभाग की वास्तविक तस्वीर चिंताजनक दिखाई देती है। एयर, रेल और सड़क कनेक्टिविटी की कमजोर स्थिति ने आम जनजीवन के साथ-साथ पर्यटन, व्यापार और निवेश की संभावनाओं को भी प्रभावित किया है। लगातार हो रही देरी और अधूरी परियोजनाएं प्रशासनिक सुस्ती और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता की ओर इशारा करती हैं।

पर्यटन और कारोबार पर कनेक्टिविटी संकट का सीधा असर- अमरकंटक, सरसी आईलैंड, बड़ी-छोटी तुम्मी, क्षीरसागर, अमोल खोह और बांधवगढ़ जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के बावजूद शहडोल संभाग पर्यटकों की प्राथमिक सूची में पीछे छूटता जा रहा है। खराब सड़कें, सीमित रेल सेवाएं और हवाई सुविधा का अभाव यहां आने-जाने को जटिल बनाता है।

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी होती तो होटल, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं में निवेश बढ़ सकता था, लेकिन वर्तमान हालात में आर्थिक गतिविधियां अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहीं।

एयरपोर्ट निर्माण डेढ़ साल से ठप - रीजनल कनेक्टिविटी योजना में शामिल शहडोल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग डेढ़ वर्ष से रुका हुआ है। परियोजना की प्रगति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनावी घोषणाओं में जिस एयरपोर्ट का जिक्र प्रमुखता से किया गया था, वह अब प्रशासनिक फाइलों तक सीमित नजर आ रहा है।

रेल विस्तार की मांगें वर्षों से लंबित - चेन्नई-बिलासपुर एक्सप्रेस को शहडोल तक बढ़ाने, मुंबई के लिए सीधी रेल सेवा और भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस को नागपुर तक विस्तार देने की मांग लंबे समय से उठती रही है। यात्रियों को आज भी अन्य स्टेशनों पर निर्भर होकर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। रेलवे स्तर पर ठोस पहल का अभाव और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता की कमी चर्चा का विषय बनी हुई है।

73 किमी हाईवे 10 साल में भी अधूरा - नेशनल हाईवे 43 पर शहडोल-उमरिया के बीच 73 किलोमीटर सड़क का निर्माण एक दशक में भी पूरा नहीं हो पाया है। टेटका मोड़ तक जर्जर सड़क शहडोल-ब्योहारी-सीधी-मऊगंज-वाराणसी मार्ग पर आवागमन को प्रभावित करती है। बार-बार शिकायतों के बावजूद निर्माण कार्य की गति धीमी बनी हुई है।

रायपुर रोड और क्षेत्रीय संपर्क भी लंबित - शहडोल-रायपुर सड़क कनेक्टिविटी को लेकर वर्षों से प्रस्ताव लंबित बताए जाते हैं। ग्रामीण अंचलों की सड़कों की मरम्मत और विस्तार भी अपेक्षित स्तर पर नहीं हो सका है। क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था में सुधार के अभाव को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।

मांगों को लेकर आशा -उषा कार्यकर्ता व पर्यवेक्षकों की हड़ताल, 10 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन

शहडोल। आशा-उषा-आशा पर्यवेक्षक एकता यूनियन, मध्यप्रदेश के बैनर तले प्रदेशभर में आज कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की। यूनियन ने मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 10 सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि आशा-उषा कार्यकर्ता एवं आशा पर्यवेक्षकों को नियमित वेतन व प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में महीनों से भुगतान लंबित है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लागू नई श्रम संहिताओं को वापस लेने तथा सभी योजना कर्मियों को श्रम कानूनों का पूर्ण लाभ देने की मांग उठाई है।

यूनियन ने आशा-उषा कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देते हुए वेतनमान और अन्य सुविधाएं प्रदान करने, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नियमित भुगतान सुनिश्चित करने, लंबित बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने तथा ऑनलाइन कार्य के लिए बेहतर गुणवत्ता के मोबाइल व पूर्ण बैलेंस उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही ऑनलाइन कार्य के अतिरिक्त मानदेय देने और रोके गए टीम बेस्ड इंसेंटिव का भुगतान करने की भी मांग की गई है।कार्यकर्ताओं का कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वे जमीनी स्तर पर मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण एवं विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, इसके बावजूद उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

पशुपालकों की आय बढ़ाने की पहल, 82 गांव होंगे क्षीरधारा योजना से लाभान्वित

विजय मत, शहडोल

उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विकास अशोक सिंह ने बताया है कि जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा क्षीरधारा ग्राम योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। योजना के पहले चरण में जिले के 82 गांवों का चयन किया गया है, जिन्हें सीधे क्षीरधारा योजना से जोड़ा जाएगा।
इस योजना के माध्यम से ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, उन्नत पशुपालन को प्रोत्साहित करने तथा पशु स्वास्थ्य एवं पोषण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चयनित गांवों में पशुपालकों को नस्ल सुधार, टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य सेवाएं, संतुलित आहार एवं आधुनिक डेयरी प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी।
पशुपालन विभाग द्वारा प्रत्येक चयनित गांव के पशुपालकों का विस्तृत प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है, जिसमें उनके पास उपलब्ध दुधारू पशुओं की संख्या, वर्तमान दुग्ध उत्पादन और आगे की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर उन्हें विभागीय योजनाओं से जोड़ते हुए अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्षीरधारा ग्राम योजना से न केवल जिले में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। योजना से जुड़े पशुपालकों को सीधे लाभ मिलेगा और दूध उत्पादन को एक नया आयाम प्राप्त होगा।

स्वीकृति के बाद भी ठप काम, श्मशान घाट और सड़क परियोजनाएं अटकीं

विजय मत, शहडोल

नगर के बाणगंगा मेला मैदान के सामने स्थित श्मशान घाट की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका ने जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) मद से बाउण्ड्रीवाल और शेड निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया था। इस कार्य के लिए 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, लेकिन बजट जारी न होने से निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है।

श्मशान घाट जैसे संवेदनशील स्थल पर आधारभूत संरचनाओं का अभाव लंबे समय से महसूस किया जा रहा है। यहां आने वाले लोगों को खुले परिसर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, जिससे मौसम की मार और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। स्वीकृति के बाद उम्मीद थी कि शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होगा, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही है।

सुरक्षा व्यवस्था और भूमि संरक्षण पर सवाल

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बाउण्ड्रीवाल का निर्माण न होने से श्मशान घाट की भूमि असुरक्षित बनी हुई है। खुले क्षेत्र में अतिक्रमण और अव्यवस्था की आशंका बनी रहती है। वहीं, शेड निर्माण से अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को राहत मिल सकती थी। लोगों का यह भी कहना है कि सार्वजनिक उपयोग के इस स्थल की अनदेखी प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर प्रश्नचिह्न लगाती है। स्वीकृत राशि के बावजूद काम शुरू न होना विकास कार्यों की गति पर असर डाल रहा है।

चार प्रमुख सड़कें भी अधूरी

डीएमएफ मद से नगर की चार प्रमुख सड़कों के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई थी। प्रत्येक सड़क की अनुमानित लागत लगभग 4 लाख रुपये बताई गई है। ये सड़कें स्थानीय यातायात को सुगम बनाने और विभिन्न वार्डों को जोड़ने में महत्वपूर्ण हैं। बजट जारी न होने के कारण इन सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ नहीं हो सका है। संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को जर्जर मार्ग और आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी

नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार तकनीकी स्वीकृतियां और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। निर्माण कार्य के लिए तैयारियां लगभग पूर्ण हैं, लेकिन धनराशि प्राप्त न होने से कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि बजट मिलते ही परियोजनाओं को गति दी जाएगी।

कार्यवाही वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन, अवैध कटाई एवं वन्यजीव तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण

पैंगोलिन-तेन्दुआ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़,15 आरोपी गिरफ्तार

विजय मत, शहडोल

वन वृत्त शहडोल के निर्देशन एवं वनमण्डल दक्षिण शहडोल की वनमण्डलाधिकारी सुश्री श्रद्धा पेंद्रे के कुशल मार्गदर्शन में वन विभाग की टीम ने अंतरजिला वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अब तक कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 1.643 किलोग्राम पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) के स्केल्स, तेन्दुआ की खाल, एक जीवित इंडियन फ्लैपशेल टर्टल तथा दो जीवित पैंगोलिन बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

लगातार सख्त कार्रवाई

27 अक्टूबर 2025 को जैतपुर परिक्षेत्र अंतर्गत बीट देवरी (ग्राम जरवाही) से दो आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुई कार्रवाई में पूछताछ के आधार पर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी, दमोह एवं कटनी जिलों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 19 जनवरी 2026 को सिवनी से तेन्दुआ की खाल जब्त की गई, जबकि 10 फरवरी 2026 को दमोह एवं शहडोल-कटनी मार्ग से जीवित पैंगोलिन के साथ आरोपियों को पकड़ा गया। पूरे प्रकरण में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना जारी है।

डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे की सक्रिय भूमिका

वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल सुश्री श्रद्धा पेंद्रे के नेतृत्व में वन विभाग द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उनके पदभार ग्रहण करने के बाद से वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन, अवैध कटाई एवं वन्यजीव तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। वे स्वयं दिन-रात वन क्षेत्रों में गश्ती कर निगरानी करती हैं, जिससे मैदानी अमले का मनोबल बढ़ा है और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगा है। स्थानीय स्तर पर भी उनकी कार्यशैली की सराहना की जा रही है।

कार्रवाई में शामिल अधिकारी-कर्मचारी

उक्त कार्रवाई में विवेचना अधिकारी जसवंत सिंह मीणा, वन परिक्षेत्र अधिकारी जैतपुर द्वारा विवेचना की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई एवं धरपकड़ में निम्न अधिकारी-कर्मचारियों का सहयोग रहा। श्रीप्रकाश शुक्ला, परिक्षेत्र सहायक बड़ेखरा, राकेश द्विवेदी, परिक्षेत्र सहायक सिंहपुर, ब्रजभान सिंह, परिक्षेत्र सहायक भुमकार, कमला प्रसाद वर्मा, परिक्षेत्र सहायक बुढ़ार, जे.पी. मौर्य, परिक्षेत्र सहायक पटना, वेदन सिंह धुर्वे, परिक्षेत्र सहायक झींक, पराग सिंह धुर्वे, परिक्षेत्र सहायक नेमुहा, अभिनय कुमार गौतम, वनरक्षक बीटगार्ड खन्नौधी, अश्वनी कुमार द्विवेदी, बीटगार्ड बहगढ़, आशीष शुक्ला, बीटगार्ड मलया, सुशील रैकवार, वनरक्षक जैतपुर
धीरेन्द्र गौतम, वनरक्षक केशवाही, बेदन सिंह धुर्वे, कार्यवाहक वनपाल केशवाही, रणदमन सिंह, वनरक्षक गोहपारू, सुजीत रजक, वनपाल प.स. घोर्वे, आशीष रैदास, वनरक्षक बीटगार्ड देवरी, सुरेश कुमार बैगा, वनरक्षक शहडोल, अविनाश सिंह, वनरक्षक शहडोल, रामकिशोर बैगा, बीटगार्ड जोधपुर, राहुल शर्मा, वनरक्षक बीटगार्ड नरवार, रवि कुमार बैगा, वनरक्षक बीटगार्ड दुलादर, रीतेन्द्र श्रीवास्तव, वनरक्षक बीटगार्ड धुरियाडोल पूर्व शबाबउल्ला खान, वनरक्षक विवेक कुमार यादव, वनरक्षक बीटगार्ड कंचनपुर वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों की सुरक्षा एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।

कमला कॉलेज में यातायात जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

सीधी। कमला स्मृति महाविद्यालय, पड़रा में यातायात जागरूकता विषय पर प्रेरक, ज्ञानवर्धक एवं गरिमामय कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भूपेश सिंह बैस (यातायात प्रभारी, सीधी), विशिष्ट अतिथि राशिरमण मिश्रा (एएसआई), संदीप पाण्डेय एवं शिवम् गौतम तथा अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉ. रोहित सिंह चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।
अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि भूपेश सिंह बैस ने कहा कि सड़क पर चलना केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से यातायात नियमों का पालन करने तथा समाज में जन-जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। सहायक प्राध्यापक नरेंद्र मिश्रा ने संयम, सतर्कता और सजगता को दुर्घटनाओं से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय बताते हुए विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान भी किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य डॉ. रोहित सिंह चौहान ने अनुशासन और जिम्मेदार नागरिकता को सुरक्षित एवं सशक्त समाज की आधारशिला बताया।

न्यूज इन शॉर्ट

लाड़ली-बहना योजना के नए पंजीयन शुरू करने की याचिका खारिज

भोपाल। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने योजना में नए रजिस्ट्रेशन शुरू करने, राशि बढ़ाकर 3000 रुपए करने और आयु सीमा में बदलाव की मांग वाली जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि योजना कब शुरू करनी है और कब बंद, यह सरकार का नीतिगत फैसला है। इसमें कोर्ट तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक कि वह पूरी तरह असंवैधानिक न हो। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने वरिष्ठ अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल के माध्यम से कोर्ट में दलील दी थी कि योजना 20 अगस्त 2023 से बंद है। उन्होंने तर्क दिया कि नए पंजीयन जो महिलाएं 20 अगस्त 2023 के बाद 21 साल की हुई हैं, उन्हें पोर्टल बंद होने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के खिलाफ है। सकलेखा ने अपनी याचिका में यह मांग भी की थी कि चुनावी वादे के मुताबिक लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों को 3000 रुपए प्रति माह के हिसाब से राशि दी जाए। उन्होंने इस योजना में न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम सीमा हटाकर जीवनपर्यंत लाभ देने की मांग भी की थी।

हम सरकार की बुद्धिमत्ता की जांच नहीं करते

शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप भार्गव ने तर्क दिया कि यह एक कार्यकारी नीति है और इसमें कोई मनमानी नहीं है। कोर्ट ने सरकार के तर्कों से सहमति जताते हुए आदेश में कहा - योजना की तारीखें तय करना राज्य का अधिकार क्षेत्र है। इसे शत्रुतापूर्ण भेदभाव नहीं माना जा सकता। न्यायालय केवल नीति की वैधता की जांच करता है, उसकी बुद्धिमत्ता की नहीं। कोर्ट ने पाया कि 21 से 60 वर्ष की आयु सीमा और पंजीकरण की समय-सीमा तय करने में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है।

यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजुद मप्र में लागू

भोपाल। यूजीसी के नए कानून को लेकर मध्यप्रदेश सर्वजन न्याय मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच के संयोजक अशोक पांडेय ने कहा कि यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है लेकिन सरकार ने 2 फरवरी को यूजीसी नियम लागू कर दिए। यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। कोर्ट से फैसला आने तक मप्र में लागू यूजीसी नियम वापस हों। मप्र में लागू किए गए यूजीसी नियम वापस हों। सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसला आने तक वापस लिया जाए। सात दिन के अंदर यूजीसी नियमों को वापस नहीं लेगी तो मध्यप्रदेश सर्वजन न्याय मंच आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। कोर्ट के निर्देश के चलते मप्र को छोड़ देश में कहीं भी यूजीसी नियम लागू नहीं किए गए।

कोर्ट के निर्देश फॉलो करें या सरकार का

मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि सरकारी आदेश से शैक्षणिक संस्थान असमंजस में हैं। उनके साथ दुविधा यह है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश फॉलो करें या सरकार का निर्देश। सिर्फ इतना चाहते हैं कि बच्चों के लिए समानता का अधिकार हो। यह व्यवस्था की जाए कि किसी भी बच्चे के साथ गलत न हो।

साढ़े तीन हजार सवालों के जवाब देगी सरकार

भोपाल। सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले विधायकों ने साढ़े तीन हजार से अधिक सवाल लगाए हैं। इन सवालों के लिखित जवाब बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार के मंत्री देंगे। विधानसभा सचिवालय के अनुसार अब तक कुल 3478 सवाल मिले हैं। इनमें 2253 प्रश्न ऑनलाइन और 1225 प्रश्न ऑफलाइन पूछे गए हैं। सभी प्रश्न अलग-अलग विभागों से संबंधित हैं, जिनके उत्तर निर्धारित तिथियों पर सदन में दिए जाएंगे।

एम.पी. ट्रांसको के 220 केवी विदिशा सबस्टेशन पर हुई सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला

भोपाल। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) की जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी के अंतर्गत विदिशा जिले के 220 केवी विदिशा सबस्टेशन पर सुरक्षा एवं सबस्टेशन संचालन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान अधीक्षण अभियंता शेखर फटाले एवं कार्यपालन अभियंता संजय श्रीवास्तव ने सबस्टेशन मेंटेनेंस एवं आपरेशन कार्यों के दौरान अपनाई जाने वाली आवश्यक सुरक्षा प्रक्रियाओं को बिंदुवार समझाया।

सुरक्षित एवं व्यवहारिक कार्य प्रणाली पर दिया जोर

कार्यशाला में कार्यस्थल पर लापरवाही रोकने के महत्व पर विशेष जोर देते हुए दुर्घटनाओं से बचाव के लिये व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी, जिससे कार्मिकों एवं उपकरणों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 293 इंजीनियर पदों को दी स्वीकृति

निर्माण केवल ईंट-पत्थर का संयोजन नहीं भविष्य की आधारशिला : सीएम मोहन

विजय मत, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि निर्माण केवल ईंट-पत्थर का संयोजन नहीं, बल्कि एक अभिनव कला है, जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की आधारशिला तैयार करती है। हर निर्माण कार्य में कन्सेप्चुअल और क्वालिटेटिव एप्रोच अनिवार्य रूप से दिखाई देनी चाहिए तथा गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश के समग्र विकास के लिए सभी को पूर्ण क्षमता और दक्षता के साथ कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को रवीन्द्र भवन में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा आयोजित एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और विभाग के तकनीकी अधिकारियों, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अभियंताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ कार्यशैली में जड़ता से बचना और बदलती तकनीकों के अनुरूप स्वयं को अद्यतन रखना समय की आवश्यकता है। ऐसी कार्यशालाएं अभियंताओं की दक्षता को परिष्कृत करती हैं और उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में दीर्घकालिक दृष्टि, पारदर्शिता और नवाचार को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

गतिशक्ति से मिलेगी नई गति: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पीएम गतिशक्ति योजना के माध्यम से अधोसंरचना विकास को नई दिशा मिली है।

आज प्रदेश के इंजीनियर्स भगवान विश्वकर्मा के साक्षात् रूप हैं, जो आधुनिक मध्यप्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में लोक निर्माण विभाग ने उल्लेखनीय कार्य कर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सड़क, पुल, स्टेडियम और शैक्षणिक परिसरों जैसे अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों में विभाग की भूमिका निर्णायक रही है। मुख्यमंत्री ने गीता के ज्ञान और विज्ञान के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि मन, बुद्धि और तत्वों के संतुलन से ही उत्कृष्ट निर्माण संभव है। उन्होंने बताया कि ग्रीन बिल्डिंग विकास को लेकर सहमति बनी है तथा एमपीआईडीसी सहित विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौते हुए हैं। विभाग के लिए 293 इंजीनियर पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

तकनीक और पारदर्शिता से बदलेगा तंत्र

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह कार्यशाला केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि विभाग की निरंतर सुधार यात्रा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, डिजिटल इंडिया और हरित विकास जैसे अभियानों के माध्यम से अधोसंरचना विकास को सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैन्युअल 2.0 को विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह सरकारी भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए समग्र मार्गदर्शिका सिद्ध होगा। कार्यशाला में अभियंताओं को आधुनिक निर्माण तकनीकों, गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यावरणीय मानकों और परियोजना प्रबंधन के नए आयामों से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समयबद्धता, गुणवत्ता और पारदर्शिता विभाग की कार्य संस्कृति का स्थायी हिस्सा बनेगी। प्रदेश का निर्माण तंत्र अब नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता के साथ नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।

केंद्रीय श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हडताल आज

विजय मत, भोपाल

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आज (गुरुवार को) देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। हडताल के कारण प्रदेश में सरकारी और निजी बैंक, बीएसएनएल, बीमा तथा डाक विभाग सहित कई केंद्रीय कार्यालयों की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि रेलवे सेवाएं सामान्य रहने की संभावना है। आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, सेवा सहित बैंक, बीमा, केंद्रीय कर्मचारी और बीएसएनएल से जुड़े संगठनों ने हड़ताल को समर्थन दिया है। भोपाल में होशंगाबाद रोड स्थित डाक भवन के सामने कर्मचारी एकत्र होकर प्रदर्शन करेंगे। इसके पहले रैली और सभा का आयोजन भी प्रस्तावित है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। इसके चलते मध्य प्रदेश की 6 हजार से अधिक बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है। क्लियरिंग स्टाफ की कमी के कारण कई स्थानों पर काम लगभग ठप रहने की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के को-ऑर्डिनेटर वीके शर्मा के अनुसार, सरकारी के साथ निजी बैंक कर्मचारी भी हड़ताल में भाग लेंगे। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक यूनियन ने समर्थन दिया है, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से हड़ताल में शामिल नहीं होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल रहेंगे, जिससे बीमा सेवाओं पर असर पड़ेगा। बीएसएनएल और डाक विभाग की सेवाएं भी प्रभावित होने की संभावना है। संगठन पदाधिकारियों के मुताबिक स्कूल-कॉलेज बंद करने का कोई आह्वान नहीं किया गया है।

हाईटेंशन बिजली टॉवर के नीचे से निकाली सार्वजनिक सड़क

विजय मत, भोपाल

राजधानी के करोंद इलाके की विनायक कॉलोनी में हाईटेंशन बिजली टॉवर के ठीक नीचे से सार्वजनिक सड़क निकाल दी गई है। घनी आबादी के बीच खड़े इस ऊंचे टॉवर के नीचे से पैदल यात्री, दोपहिया और चारपहिया वाहन गुजरते हैं। स्थानीय लोग इसे तंज कसते हुए 'भोपाल का एफिल टॉवर' कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह सड़क रोजाना खतरे के साये में गुजरती है। शुरुआत में यह इलाका खाली था, लेकिन समय के साथ यहां मकान बन गए और आबादी बढ़ती चली गई। अब स्थिति यह है कि टॉवर और हाईटेंशन लाइन के ठीक नीचे से लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भारी वाहन यहां से नहीं निकल पाते और बारिश के दिनों में बिजली करंट फैलने का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता है। उनका कहना है कि राजधानी में इस तरह की लापरवाही गंभीर हादसे को न्योता दे सकती है।यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब शहर में पहले 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग ब्रिज और छोटे मेट्रो स्टेशन जैसी संरचनाएं चर्चा का विषय बन चुकी हैं। अब हाईटेंशन टॉवर के नीचे बनी यह सड़क भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर योजना और सुरक्षा मानकों का पालन कितना हो रहा है। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक टॉवर को शिफ्ट करने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी और जमीन संबंधी दिक्कतों के कारण फैसला लंबित है।

11वीं की छात्रा से रेप के आरोपी का सनसनीखेज खुलासा

आरोपियों ने छात्रा संग 4 कारों में किया दुष्कर्म, वीडियो बना किया ब्लैकमेल

विजय मत, भोपाल

भोपाल में 11वीं की छात्रा से रेप केस में आरोपी माज खान के खुलासों ने पुलिस को चौंका दिया है। उसने बताया है कि ओसाफ अली खान ने थार में नाबालिग से रेप किया। इस दौरान वह बाहर खड़ा था। उसी ने छिपकर वीडियो शूट किया है। आरोपी माज खान ने बताया कि मैंने प्लानिंग पहले ही कर ली थी। कार के बाहर खड़े रहकर ग्लास से अंदर झांका और चोरी छिपे वीडियो शूट कर लिया। वीडियो को आपस में शेयर किया। लड़की को संबंध बनाने के लिए कई बार मजबूर किया। यहां तक कि वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर छात्रा से 40 हजार रुपए भी वसूल लिए। इधर छात्रा से खानूगांव में जिस थार में पहली बार रेप किया गया था। पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है। कार को सीहोर जिले

के एक गांव में माज ने छिपा दिया था। माज खान ही थार सहित चार कारों का इस्तेमाल करता था। इन चारों कारों में छात्रा से अलग-अलग समय में अलग-अलग स्थानों पर रेप किया है। बता दें 365 जिम का संचालक माज खान 13 फरवरी तक कोहेफिजा थाना पुलिस की रिमांड पर है। उसे 8 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस अन्य छात्राओं से भी रेप, ब्लैकमेलिंग के संबंध में पूछताछ कर रही है। वहीं मुख्य आरोपी ओसाफ अली खान (19) को जेल भेज दिया गया है।

करीबियों की तलाश, मोबाइल अब तक नहीं मिला

पुलिस ने बताया कि जिस आईफोन से छात्रा के रेप के वीडियो शूट किए गए, वह माज का ही था। इसे माज ने राजस्थान में तोड़कर फेंकने की बात कही है। वह लगातार अपनी बात पर कायम है। पुलिस उसके मोबाइल फोन को अब भी जब्त नहीं कर सकी है। माज के दो अन्य करीबियों की पुलिस तलाश कर रही है। कई बार पूछताछ के लिए बुलाने पर भी ये दोनों थाने नहीं पहुंचे हैं। लिहाजा, पुलिस को यकीन हो चला है कि दोनों की भूमिका भी केस में संदिग्ध रही है। इसी के चलते वह पुलिस से भाग रहे हैं। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अब तक कोई दूसरी पीड़िता सामने नहीं आई है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

राज्यपाल के अभिभाषण में हकीकत से दूर आंकड़ों का आडंबर: पटवारी

विजय मत, भोपाल

मध्यप्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के पहले सियासत गरमा गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम डॉ. मोहन को पत्र लिखा है। पटवारी ने पत्र में लिखा है कि आपकी सरकार के बजट सत्र में ऐसे मंत्री उपस्थित रहेंगे जिनकी मंत्री मंडल में उपस्थिति अब उपयोगिता से उत्तर मांग रही है। मंत्री विजय शाह पर देश की बेटी और भारतीय सेना के अपमान के गंभीर आरोप हैं। छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप से दर्जनों मासूम बच्चों की मौत हुई लेकिन स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला भी बजट सत्र में शामिल होंगे। इंदौर में दूषित पानी से कई लोगों की मौत हुई , कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होंगे। यह शर्मनाक की ऐसे मंत्री अभी भी पद पर बने हुए हैं। जीतू पटवारी ने लिखा - यह भी सर्वविदित है की राज्यपाल के अभिभाषण में हकीकत से दूर आंकड़ों का आडंबर प्रस्तुत किया जाएगा। कांग्रेस ने बजट सत्र के पहले प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा- एमपी सरकार पर 5 लाख करोड़ का कर्ज है, हर व्यक्ति पर 60 हजार।

सरकार की 29 योजनाएं बंद

यह लोग नुकसान ही पहुंचाने का काम करेंगे। मध्यप्रदेश सरकार की 29 योजनाएं बंद हो गई हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है। हड़ताल करने वाले संगठनों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने झुककर डील की है। मक्का ज्वार हम पैदा करते हैं, वो भी अब उनसे खरीदा जाएगा। किसान, ट्रेड यूनियन, कर्मचारी सभी हड़ताल कर रहे हैं। पेंशनर, युवा, महिला सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हर वर्ग परेशान है।

मध्य प्रदेश में 16 फरवरी को हड़ताल पर नापतौल विभाग

भिंड निरीक्षक से अभद्रता की घटना ने पकड़ा तूल

विजय मत, भोपाल

भिंड जिले में नापतौल निरीक्षक सौरभ शर्मा के साथ पेट्रोल पंप संचालक द्वारा गाली-गलौज और धमकी दिए जाने के मामले ने अब प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया है। कार्रवाई न होने से नाराज मध्य प्रदेश के नापतौल अधिकारी और कर्मचारी सोमवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और पूरे प्रदेश में कामकाज बंद रखेंगे। मध्य प्रदेश नापतौल अधिकारी कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि भिंड के दीनपुरा स्थित यादव फिलिंग सेंटर के मालिक सुरेंद्र यादव ने निरीक्षक सौरभ शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार किया और धमकी दी। घटना के बाद संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इससे विभाग के कर्मचारियों और

अधिकारियों में भारी आक्रोश है।

3 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो हड़ताल: नापतौल विभाग के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन के अंदर पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई नहीं होती तो सोमवार को पूरे प्रदेश में नापतौल विभाग का कामकाज ठप रहेगा। पहले चरण में एक दिन का सामूहिक अवकाश रहेगा। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।

कर्मचारी संघ ने लगाया पुलिस पर दबाव का आरोप

कर्मचारी संघ का आरोप है कि पेट्रोल पंप मालिक प्रभावशाली होते हैं, जिसके कारण अब तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए है और यदि एक सरकारी निरीक्षक को ही गंदी गालियां सुननी पड़े तो वह निष्पक्ष तरीके से काम कैसे करेगा। इससे पूरे प्रदेश का माहौल खराब होगा।

कलेक्टर और एसपी को दी सूचना

मध्य प्रदेश नाप तौल विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि संघ की ओर से कलेक्टर भिंड और एसपी को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जानकारी दी गई है। इसके साथ ही विभागीय नियंत्रक और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि ड्यूटी के दौरान किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ गाली-गलौज होगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नए लेबर लॉ के खिलाफ भोपाल में बैंक के बाहर धरना-प्रदर्शन

चारों श्रम संहिताएं वापस लेने की मांग

विजय मत, भोपाल

नए लेबर कानूनों के विरोध में भोपाल में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने धरना-प्रदर्शन किया और चारों श्रम संहिताएं वापस लेने की मांग की। शहर में सामान्य जनजीवन पर सीमित असर रहा, लेकिन यूनियनों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार श्रमिकों से संवाद किए बिना कानून लागू कर रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं के विरोध में गुरुवार को राजधानी भोपाल में कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के आह्वान पर बैंक, बीमा, बीएसएनएल, डाक विभाग, केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और विभिन्न श्रमिक यूनियनों से जुड़े कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए।शहर में पंजाब नेशनल बैंक के सामने कर्मचारियों ने धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

किन संगठनों ने लिया हिस्सा

आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, सेवा सहित कई ट्रेड यूनियनों ने प्रदर्शन का समर्थन किया। बैंक और बीमा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की भी भागीदारी रही। कुछ संगठनों ने प्रतीकात्मक रूप से काम बंद कर विरोध जताया, जबकि कुछ ने समर्थन दर्ज कराते हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

विजय मत एंकर कुबेरेश्वर धाम... रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर 2000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात

14 से 20 फरवरी तक शिवमय होगा सीहोर, हाईटेक निगरानी लागू

विजय मत, सीहोर

विश्व प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम एक बार फिर भक्ति और आस्था का विराट केंद्र बनने जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के सान्निध्य में 14 से 20 फरवरी तक आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की है। बीते वर्षों में उमड़ी रिकॉर्ड भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए इस बार पहले से अधिक सुदृढ़ सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है। महोत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए छह जिलों से भारी पुलिस बल बुलाया गया है। बाहर से आए 889 पुलिसकर्मियों सहित स्थानीय पुलिस, होमगार्ड, वन एवं आबकारी विभाग के कर्मचारियों को मिलाकर कुल 1235 अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कोटवार, ग्राम रक्षा समिति और वॉलेंटियर्स को जोड़कर लगभग 2000 सुरक्षाकर्मी पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभालेंगे। पूरे आयोजन पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की सीधी नजर रहेगी। पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अनाउंसमेंट सिस्टम को दुरुस्त कर लिया गया है। प्रशासन का दावा है कि इस बार रुद्राक्ष महोत्सव भक्ति और सुरक्षा के अद्भुत संगम का उदाहरण बनेगा।

छह जिलों से पहुंचा बल

इंदौर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह और जबलपुर सहित विभिन्न जिलों से पुलिस बल की आमद हुई है। आरएपीटीसी इंदौर, पीटीएस 15वीं वाहिनी विसबल इंदौर, डीजीपी रिजर्व मुरैना सहित अन्य इकाइयों के जवान मोर्चा संभालेंगे। 10 राजपत्रित अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि गुरुवार से संपूर्ण बल कुबेरेश्वर धाम क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। आयोजन स्थल, मंदिर परिसर और हाईवे मार्गों पर अलग-अलग प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक पिकेट और चेक पॉइंट पर जवानों की ड्यूटी तय की गई है। महिला पुलिस बल की अलग टीम कथा स्थल, मंदिर परिसर और पार्किंग क्षेत्रों में निगरानी रखेगी।

ट्रैफिक डायवर्जन लागू, हाईटेक निगरानी और कंट्रोल रूम

गुरुवार सुबह 6 बजे से इंदौर-भोपाल हाईवे पर विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है जो कि 21 फरवरी सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जाएगा, जबकि छोटे वाहनों के लिए अलग रूट तय किया गया है। केवल धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सीधे हाईवे से प्रवेश की सुविधा रहेगी। सभी प्रमुख चौराहों, डायवर्जन पॉइंट्स और पार्किंग क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग होगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए क्रेन, गैस कटर और मैकेनिकों की भी व्यवस्था की गई है। त्वरित सूचना आदान-प्रदान हेतु अधिकारियों का विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है।

संस्थापक
श्री रामसिपाही शुक्ल

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक बदलाव के प्रेरणास्रोत थे दयानंद

आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद के विचारों में धर्म, विज्ञान, समाज सुधार और राष्ट्रवाद का समन्वय था। अंग्रेजी राज के दौरान उन्होंने वेद, स्वदेशी, नारी शिक्षा व समानता का समर्थन किया वहीं अंधविश्वास व जातिप्रथा का विरोध किया। आज भी उनके विचार प्रासंगिक व प्रेरक हैं।

महर्षि दयानंद सरस्वती ने जीवन भर हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई। इस संन्यासी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान भी भारतीय संस्कृति की रक्षा की और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हालांकि, सुधारवादी विचारों के चलते उनके कुछ शत्रु भी बन गये। 30 अक्टूबर, 1883 को अजमेर में उनकी हत्या कर दी गई, संभवतः जहर देकर। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज फला-फूला और आज दुनिया में लाखों अनुयायी हैं।21वीं सदी में, जब दुनिया वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और सामाजिक परिवर्तनों से गुजर रही है, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं व मार्गदर्शक का काम करते हैं। सबसे पहले, दयानंद सरस्वती ने महिलाओं को शिक्षा और समान अधिकार देने की बात की, जिसकी आज भी देश में लैंगिक असमानता के खिलाफ लड़ाई में प्रासंगिकता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में जेंडर इक्वेलिटी शामिल है, और दयानंद के विचार इस दिशा में प्रेरक हैं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध किया, जो आज भी कानूनी और सामाजिक मुद्दे हैं।

महर्षि दयानंद ने शिक्षा पर बल दिया व उसे हरेक जाति और महिला-पुरुषों सभी के लिए अनिवार्य बताया। आज के भारत में, जहां साक्षरता दर बढ़ रही है लेकिन गुणवत्ता में कमी है, उनके वैदिक शिक्षा के मॉडल उपयोगी हैं जो नैतिकता, विज्ञान और तर्क पर आधारित हैं। आर्य समाज द्वारा स्थापित डीएवी स्कूल आज भी शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, जो उनके विचारों की व्यावहारिकता का प्रमाण हैं।तीसरा, दयानंद सरस्वती ने कहा कि जन्म से नहीं, कर्म से जाति निर्धारित होती है। आज भारत में आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों में यह विचार प्रासंगिक है। समाज के वंचित-पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए उनके जैसे सुधार आवश्यक हैं।

सूचना

सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख-आलेख एवं विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं। अतः यह जरूरी नहीं है कि विजय मत समूह उपरोक्त लेख या विचारों से सहमत हो। किसी लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार हैं।

बांग्लादेश आज अपने इतिहास के एक अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर

कांतिलाल मांडोत

> रोसे का संकेत होगा।
> अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस चुनाव पर नजर रखे हुए है। दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए बांग्लादेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत के साथ उसके संबंध रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अहम हैं। शेख हसीना के भारत में रहने के कारण यह चुनाव द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो गया है। नई सरकार की नीतियां क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं।
> आम मतदाता के लिए यह चुनाव केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा प्रश्न है। आर्थिक चुनौतियां बेरोजगारी महंगाई और सामाजिक असुरक्षा लोगों की प्राथमिक चिंताएं हैं। यदि नई सरकार इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने में विफल रहती है तो असंतोष और बढ़ सकता है। इसलिए मतदाता केवल विचारधारा नहीं है।

बांग्लादेश आज अपने इतिहास के एक अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। तेरहवें आम चुनाव के लिए हो रहा मतदान केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह उस दिशा का निर्धारण भी है जिस ओर यह दक्षिण एशियाई राष्ट्र आगे बढ़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने और भारत में शरण लेने के बाद यह पहला राष्ट्रीय चुनाव है। ऐसे समय में जब राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर है और समाज में अविश्वास गहराया हुआ है तब यह चुनाव लोकतंत्र की परीक्षा भी है और सामाजिक सौहार्द की भी।

देश के लगभग बारह करोड़ अस्सी लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान के लिए सफेद मतपत्र नई सरकार के चयन हेतु है जबकि पिंक मतपत्र के माध्यम से जुलाई नेशनल चार्टर नामक संवैधानिक संशोधन पर भी जनमत लिया जा रहा है। इस दोहरे मतदान ने चुनाव को और अधिक निर्णायक बना दिया है। एक ओर सरकार चुनने की प्रक्रिया है तो दूसरी ओर संविधान की आत्मा में परिवर्तन का प्रस्ताव है। ऐसे में यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि राष्ट्र की विचारधारा की दिशा तय करने वाला जनमत संग्रह बन गया है।

चुनावी माहौल में डर और असुरक्षा की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। विशेषकर हिंदू समुदाय के बीच भविष्य को लेकर गहरी चिंता है। पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाओं ने इस आशंका को और बढ़ाया है। विभिन्न जिलों में मंदिरों पर हमले हुए हैं दुकानों में आगजनी हुई है और समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं। रंगपुर में सुसेन चंद्र सरकार की हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। खुलना में मंदिर में तोड़फोड़ की गई। चटगांव में दीपक साहा की दुकान को लूटा गया और आग के हवाले कर दिया गया। लालमोनिरहाट में एक शिक्षक के परिवार पर हमला हुआ। बरिसाल में गौरव दास को चुनावी रैली के बाद चाकू मारा गया। इन घटनाओं ने चुनाव को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा बना दिया है।

राजनीतिक परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव आया है। लंबे समय तक सत्ता में रही अवामी लीग इस चुनाव में मुख्य दावेदार के रूप में नहीं दिख रही। मैदान में मुख्य रूप से बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी और जमात ए इस्लामी के नेतृत्व वाला गठबंधन है। बीएनपी का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथों में है। अधिकांश सर्वेक्षणों में बीएनपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर जमात ए इस्लामी एक व्यापक गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है जिसमें नवगठित नेशनल सिटिजन पार्टी भी शामिल है। इस गठबंधन की वैचारिक दिशा को लेकर समाज में बहस तेज है क्योंकि जमात लंबे समय तक प्रतिबंधित रही और उस पर कट्टरपंथी एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहे हैं।

हिंदू समुदाय के कई लोग खुद को राजनीतिक रूप से असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि मुख्य दलों में कोई भी स्पष्ट रूप से उदारवादी या मध्यममार्गी दृष्टिकोण लेकर सामने नहीं आया है। कुछ मतदाता बीएनपी को अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं जबकि जमात के प्रभाव को लेकर आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ढाका के एक मतदाता ने कहा कि वे ऐसे दल को वोट देंगे जो देश को धार्मिक कट्टरता की ओर न ले जाए। यह भावना केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस वर्ग की है जो स्थिरता और समान अधिकारों की गारंटी चाहता है।

चुनाव आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। लगभग डेढ़ लाख से अधिक पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। करीब एक लाख सैनिक भी विभिन्न क्षेत्रों में तैनात हैं। देश के आधे से अधिक मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं। एक क्षेत्र में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया है। इन व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि प्रशासन संभावित हिंसा को लेकर सतर्क है।

चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसक घटनाएं स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच राजनीतिक झड़पों में कई लोगों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए। मानवाधिकार संगठनों ने पिछले डेढ़ वर्ष में राजनीतिक हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और हजारों के घायल होने की जानकारी दी है। यह आंकड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरे सवाल खड़े करते हैं। यदि चुनाव हिंसा की छाया में होगा तो उसकी वैधता पर भी प्रश्न उठेंगे।

इस बार का चुनाव एक वैचारिक संघर्ष भी है। क्या बांग्लादेश अपने संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावाद को बनाए रखेगा या धार्मिक पहचान को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वीकार करेगा। पिंक मतपत्र के माध्यम से प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन इसी दिशा का संकेत देगा। यदि मतदाता बड़े पैमाने पर संशोधन का समर्थन करते हैं तो देश की राजनीतिक संरचना में दीर्घकालिक परिवर्तन संभव है। यदि वे इसे अस्वीकार करते हैं तो यह वर्तमान व्यवस्था पर भरोसे का संकेत होगा।अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस चुनाव पर नजर रखे हुए है। दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए बांग्लादेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत के साथ उसके संबंध रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अहम हैं। शेख हसीना के भारत में रहने के कारण यह चुनाव द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो गया है। नई सरकार की नीतियां क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं।

आम मतदाता के लिए यह चुनाव केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा प्रश्न है। आर्थिक चुनौतियां बेरोजगारी महंगाई और सामाजिक असुरक्षा लोगों की प्राथमिक चिंताएं हैं। यदि नई सरकार इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने में विफल रहती है तो असंतोष और बढ़ सकता है। इसलिए मतदाता केवल विचारधारा नहीं बल्कि शासन क्षमता को भी परख रहे हैं।

बांग्लादेश ने अपने स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सैन्य शासन से लोकतंत्र की ओर वापसी और फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण का दौर देश की यात्रा का हिस्सा रहा है। आज का चुनाव उसी यात्रा का नया अध्याय है। यह तय करेगा कि देश समावेशी लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ेगा या वैचारिक टकराव की ओर जाएगा।मतदान के परिणाम चाहे जो भी हों एक बात स्पष्ट है कि बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक विश्वास की पुनर्स्थापना है। यदि राजनीतिक दल चुनाव के बाद भी संवाद और सहमति की राजनीति अपनाते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होगा। यदि प्रतिशोध और विभाजन की राजनीति हावी रही तो अस्थिरता बढ़ सकती है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)- साभार

बोलियों, भाषाओं का एक विश्व प्रसिद्ध अभूतपूर्व संगम

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

भारत माता की गोद में एक से बढ़कर एक अनेक ऐसी खूबसूरत उपलब्धियां, हजारों वर्ष पूर्व से उपलब्ध है जिनकी अणखुट संरचना, प्राकृतिक खूबसूरती, विशाल भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं के साहित्यग्रंथों सहित अनेक अपार क्षमता वाली बौद्धिक संपदा का विशाल भंडार देख संपूर्ण विश्व हैरान था जिसपर नज़र लग गई थी जिससे हजारों वर्षो की गुलामी से आजादी के बाद 1947 में भारत का विभाजन हुआ। साथियों फ़िर भी हम अपनी मेहनत, लगन से फिर अपनी ताकत, ज़ाज़बे और जांबाज़ी के साथ वैश्विक पटल पर प्रमुख हस्ती के रूप में अपने हर क्षेत्र की समृद्धि व ताकत के आगाज़ के साथ वैश्विक पटल पर अहम स्थान रखते हैं, जिसे देखकर विश्व की नजरें फिर भारत की ओर आकस्मिकता से देश भारत का लोहा मान रही है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि आज भारत उस स्थिति में है जहां भारत की ओर नज़र लगाने वाले को हज़ार बार सोचना पड़ेगा, यह है हमारा आज का भारत !साथियों बात अगर हम अपनी संस्कृति, विशाल मातृभाषा और भारतीय भाषाओं के साहित्यग्रंथों की करें तो यह हमारी पहचान है। यूं तो भारत में बावीस भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है परंतु पूरे भारत की बात करें तो यहां भाषाएं व उपभाषाएं हजारों की संख्या में होंगी, जिसकी रक्षा करना और विलुप्तता से बचाने की ज़वाबदारी हमारे आज के युवाओं के ऊपर है क्योंकि आज हमारे देश की 68 प्रतिशत आबादी युवा है और इस युवा भारत के युवाओं को ही हमारी संस्कृति, भाषाओं को जीवित रखना है। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा को महत्व देना होगा और अपने समाज, घर, क्षेत्र में अपनी मातृभाषा में बात करना होगा ताकि उसे हम विलुप्तता से बचा सके, आज इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई है, क्योंकि आज के बदलते परिवेश में हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचलन कुछ तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर के युवाओं में इसका क्रेज अधिक महसूस किया जा रहा है जो बड़े शहरों से होकर अब हमारे छोटे शहरों गांवों में भी फैलने की संभावना बढ़ गई है। जिसका संज्ञान बुजुर्गों को लेना होगा और युवाओं को अपनी मातृभाषा में बोलने, संस्कृति, साहित्यग्रंथों, भाषाओं की तरफ ध्यान आकर्षित कराकर उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन देना होगा ताकि धरोहर को विलुप्तता से बचाया जा सके।

(यह लेखक के निजी विचार हैं) -साभार

सही दिशा में चलना अब विकल्प ही नहीं ज़रूरत भी है

अरविन्द श्रीवास्तव

> शहरों में फुटपाथों की कमी एक सच्चाई है। हर जगह तुरंत बेहतर इंफ्रास्ट बन जाए, यह संभव नहीं। ऐसे में पैदल यात्रियों के पास खुद को सुरक्षित रखने का सबसे सरल उपाय यही है कि वे सही दिशा में चलें। यह नियम किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं है। अलग-अलग राज्यों की ट्रैफिक गाइडलाइंस और अदालतों के फैसले इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। संदेश साफ है कि जहां पैदल चलने की अलग व्यवस्था नहीं है, वहां दाईं ओर चलना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें नियम पता ही नहीं था। लेकिन जानकारी का अभाव अब बहाना नहीं रह गया है। अखबार, सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में यह मुद्दा सामने आ चुका है। अब सवाल यह नहीं कि नियम क्या है, सवाल यह है कि क्या हम उसे अपनाने को तैयार हैं।

सड़क पर चलते हुए हम अक्सर यह मान लेते हैं कि नियम सिर्फ गाड़ियों के लिए होते हैं। पैदल चलना तो सबसे सरल काम है, इसमें भला नियम क्या होंगे? लेकिन यही सोच हर साल हजारों जिंदगियों की कीमत बन जाती है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में बड़ा हिस्सा पैदल यात्रियों का है। यह केवल तेज रफ्तार या लापरवाही से वाहन चलाने का नतीजा नहीं, बल्कि पैदल चलने के गलत तरीकों का भी गंभीर परिणाम है। बचपन से हमें सिखाया गया कि ÷सड़क पर बाएं चलो÷, यह सीख इतनी गहरी बैठ गई कि हमने कभी उस पर सवाल ही नहीं उठाया। समय बदला, ट्रैफिक बढ़ा, सड़कें तेज हुईं, लेकिन हमारी आदतें वहीं की वहीं रहीं। अब वक्त आ गया है कि हम इस अधूरी सीख को पूरा करें और समझें कि पैदल यात्रियों के लिए सही दिशा कौन-सी है।जहां सड़क पर फुटपाथ नहीं है, वहां पैदल यात्रियों को दाईं ओर चलना चाहिए। इसका कारण बेहद सीधा और जीवनरक्षक है। जब आप दाईं ओर चलते हैं तो सामने से आने वाले ट्रैफिक को देख सकते हैं। खतरा आपकी आंखों के सामने होता है, पीठ पीछे नहीं। सामने से आती गाड़ी की गति, दूरी और ड्राइवर का व्यवहार देखकर आप समय रहते किनारे हो सकते हैं। इसके उलट जब आप बाईं ओर चलते हैं तो वाहन पीछे से आते हैं। हॉर्न सुनाई न दे, मोबाइल पर ध्यान चला जाए या सड़क पर शोर हो, तो पीछे से आई तेज रफ्तार गाड़ी जानलेवा साबित हो सकती है। दाईं ओर चलने का नियम डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है।

दुनिया के कई देशों में यह बात सामान्य समझ का हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ब्रिटेन का हाईवे कोड और कई अंतरराष्ट्रीय रोड सेफ्टी गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि जहां फुटपाथ न हो, वहां हमेशा ट्रैफिक के विपरीत दिशा में चलना चाहिए। भारत में भी ट्रैफिक विशेषज्ञ, अदालतें और रोड सेफ्टी कमेटियां यही मानती हैं कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा का सबसे बुनियादी नियम यही है। इसके बावजूद आम लोगों में भ्रम बना हुआ है। शायद इसलिए क्योंकि हमने इसे कभी गंभीरता से अपनाया ही नहीं। हमें लगता है कि यह केवल कागजी नियम हैं, लेकिन जब हादसा होता है तब यही नियम जीवन और मृत्यु के बीच फर्क बन जाते हैं।

यह सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह कानूनी और आर्थिक पहलू से भी जुड़ा है। अगर कोई पैदल यात्री गलत साइड चलते हुए दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसे आंशिक रूप से अपनी लापरवाही का जिम्मेदार माना जा सकता है। कई मामलों में मुआवजा या बीमा क्लेम कम कर दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गलत दिशा में चलना न केवल जान जोखिम में डालता है, बल्कि दुर्घटना के बाद न्याय और आर्थिक सहायता की राह भी मुश्किल बना देता है। सड़क पर सही चलना अब सिर्फ समझदारी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है।

समस्या यह नहीं कि नियम मौजूद नहीं हैं, समस्या यह है कि हम उन्हें आदत में नहीं ढाल पाए हैं। बचपन से जो सीख मिली, वही हमारी चाल में बस गई। सड़क पार करते समय तो हम दाएं-बाएं देखते हैं, लेकिन चलते समय सोचते ही नहीं कि किस तरफ चल रहे हैं। आदतें रातों-रात नहीं बदलतीं। इसके लिए अभ्यास चाहिए, खुद को याद दिलाना पड़ता है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लोग टोकेंगे भी, लेकिन हर सही आदत की शुरुआत थोड़ी असहज होती है। जब हेलमेट पहनना अनिवार्य हुआ था, तब भी लोगों को अटपटा लगा था। आज वही हेलमेट जान बचाने का सबसे बड़ा साधन है। दाईं ओर चलने की आदत भी धीरे-धीरे उतनी ही स्वाभाविक हो सकती है।इसके लिए सिर्फ सरकार या पुलिस को दोष देना आसान है, लेकिन समाधान हमारे हाथ में भी है। जब हम खुद सही चलेंगे, तभी बच्चे देखकर सीखेंगे। आज जो बच्चा अपने माता-पिता के साथ सड़क पर चलता है, वही कल का पैदल यात्री होगा। अगर वह हमें गलत साइड चलते देखेगा, तो वही सीखेगा। सड़क सुरक्षा का सबसे मजबूत पाठ स्कूलों और किताबों से पहले व्यवहार से आता है। घर से निकलते समय अगर हम खुद को यह याद दिला लें कि आज मुझे दाईं ओर चलना है, तो यह छोटी-सी सोच बड़ी सुरक्षा बन सकती है।

शहरों में फुटपाथों की कमी एक सच्चाई है। हर जगह तुरंत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, यह संभव नहीं। ऐसे में पैदल यात्रियों के पास खुद को सुरक्षित रखने का सबसे सरल उपाय यही है कि वे सही दिशा में चलें। यह नियम किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं है। अलग-अलग राज्यों की ट्रैफिक गाइडलाइंस और अदालतों के फैसले इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। संदेश साफ है कि जहां पैदल चलने की अलग व्यवस्था नहीं है, वहां दाईं ओर चलना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।

अक्सर लोग कहते हैं कि हमें नियम पता ही नहीं था। लेकिन जानकारी का अभाव अब बहाना नहीं रह गया है। अखबार, सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में यह मुद्दा सामने आ चुका है। अब सवाल यह नहीं कि नियम क्या है, सवाल यह है कि क्या हम उसे अपनाने को तैयार हैं। सड़क पर चलते हुए एक कदम दाईं ओर ले जाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अपनी पुरानी आदत को छोड़ना। लेकिन अगर इस बदलाव से किसी की जान बच सकती है, तो यह मेहनत बहुत छोटी है।

सड़कें साझा जगह हैं। वहां वाहन चालक, पैदल यात्री, साइकिल सवार सभी एक-दूसरे पर निर्भर हैं। सुरक्षा तभी संभव है जब हर कोई अपनी भूमिका समझे। वाहन चालकों को सतर्क रहना होगा, लेकिन पैदल यात्रियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सही दिशा में चलना उसी जिम्मेदारी का पहला कदम है। यह न तो डर का नियम है और न ही सजा का, यह जीवन का नियम है।

अंत में यही कहा जा सकता है कि सही दिशा में चलना कोई बड़ा बलिदान नहीं मांगता। यह बस थोड़ी-सी जागरूकता, थोड़ी-सी प्रैक्टिस और थोड़े-से धैर्य की मांग करता है। अगर हम आज से यह तय कर लें कि जहां फुटपाथ नहीं है, वहां हम दाईं ओर चलेंगे, तो शायद कल किसी परिवार को अपनों को खोने का दुख न झेलना पड़े। जान बचाने के लिए दिशा बदलनी पड़े, तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब देर किस बात की है, आइए सही दिशा में चलने की आदत डालें और सड़क को थोड़ा और सुरक्षित बनाएं। (यह लेखक के निजी विचार हैं)- साभार

शब्द पहेली - 8637

1		2	3	■	4	5		6
	■	7		8			■	
9	10	■	■		■	■	11	
12		■	13		14	■	15	
■	16			■	17			■
18		■	19	20		■	21	22
23		■	■		■	■	24	
	■	25	26		27	28	■	
29				■	30			

बाएँ से दाएँ

1. घूमना-फिरना-4
4. पक्षियों का शोर-4
7. धोखाधड़ी, मक्कारी-5
9. भस्म, खाक -2
11. आज्ञापालक, कर्मचारी-2
12. मगन, लीन-2
13. नेत्रावरण-3
15. त्याग, दक्षिणा-2
16. जीभ, जिव्हा-3
17. मक्खन-3
18. पेड़ का मध्य व मोट भाग-2
19. गर्भ-3
21. निवास, रहना-2
23. भाग्य (अंग्रेजी-2)
24. पानी, नीर-2
25. इच्छा पूर्ति करना-5
29. एक मुस्लिम महीना-4
30. भाग्य, नसीब-4

ऊपर से नीचे

1. अनबन, झगड़ा-4
2. भालू-2
3. परिणाम-2
4. प्याला-2
5. बालों का गुच्छा-2
6. वर, इच्छापूर्ति-4
8. नीरज, जलज-3
10. भयानक-5
11. दयालु-5
13. आश्रय, शरण-3
14. करिश्मा, करतब-3
18. तहखाना-4
20. मगरमच्छ-3
22. शलवार, पायजामा-4
25. आनंद-2
26. झुका हुआ-2
27. पत्र, चिट्ठी-2
28. नासिका, घ्राणेंद्रिय-2

शब्द पहेली -8636 का हल

■	ल	बा	दा	■	स	ल	वा	र
प	■	■	न	सी	ब	■	■	त
ल	■	र	वी	■	क	ल	■	ज
क	म	त	र	ता	■	त	म	गा
■	द	■	ता	■	रा	■	ग	■
म	न	का	■	मो	ह	त	र	मा
र	■	ला	र	■	दे	र	■	म
ह	■	■	प	र	ख	■	■	ला
म	र	घ	ट	■	ना	पा	क	■

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

13 फरवरी 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	मकर में	कुंभ	06.37 बजे से
चंद्र	धनु में	मीन	08.10 बजे से
मंगल	मकर में	मेष	09.41 बजे से
बुध	कुंभ में	वृष	11.21 बजे से
गुरु	मिथुन में	मिथुन	13.19 बजे से
शुक्र	कुंभ में	कर्क	15.32 बजे से
शनि	मीन में	सिंह	17.48 बजे से
राहु	कुंभ में	कन्या	20.00 बजे से
केतु	सिंह में	तुला	22.11 बजे से
राहुकाल	10.30 से 12.00 बजे तक	वृश्चिक	00.26 ब.से
		धनु	02.42 बजे से
		मकर	04.47 बजे से

शुक्रवार 2026 वर्ष का 44 वा दिन
दिशाशूल पश्चिम ऋतु शिशिर।
विक्रम संवत् 2082 शक संवत् 1947
मास फाल्गुन (दक्षिण भारत में माघ)
पक्ष कृष्ण
तिथि एकादशी 14.26 बजे को समाप्त।
नक्षत्र मूल 16.13 बजे को समाप्त।
योग वज्र 03.24 बजे रात्र को समाप्त।
करण बालव 14.26 बजे तदनन्तर कौलव 03.18 बजे रात्र को समाप्त।
चन्द्रायु 24.2 घण्टे
रवि क्रान्ति दक्षिण 13° 26'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1872619
जूलियन दिन 2461084.5
कलियुग संवत् 5126
कल्पारंभ संवत् 1972949123
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885123
वीरनिर्वाण संवत् 2552
हिजरी सन् 1447
महीना सावान तारीख 24
विशेष विजया एकादशी व्रत।

दिन का चौघड़िया				रात का चौघड़िया			
चर	05.55	से 07.23	बजे तक	रोग	05.38	से 07.1	बजे तक
लाभ	07.23	से 08.51	बजे तक	काल	07.11	से 08.43	बजे तक
अमृत	08.51	से 10.19	बजे तक	लाभ	08.43	से 10.15	बजे तक
काल	10.19	से 11.47	बजे तक	उद्वेग	10.15	से 11.47	बजे तक
शुभ	11.47	से 01.15	बजे तक	शुभ	11.47	से 01.19	बजे तक
रोग	01.15	से 02.43	बजे तक	अमृत	01.19	से 02.51	बजे तक
उद्वेग	02.43	से 04.10	बजे तक	चर	02.51	से 04.23	बजे तक
चर	04.10	से 05.38	बजे तक	रोग	04.23	से 05.55	बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, मध्यम चर, अशुभ उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

विजय मत
राष्ट्र को समर्पित
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र
www.vijaymat.com
भोपाल, शुक्रवार , 13 फरवरी 2026

न्यूज इन शॉर्ट

महाशिवरात्रि पर तुर्राधाम में निकलेगी भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात

अनूपपुर। जिले के अंतिम छोर पर स्थित नगर परिषद डोला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तुर्राधाम में महा शिवरात्रि के पावन अवसर पर इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ की भव्य शोभायात्रा (बारात) बड़े ही श्रद्धा, उत्साह और धूमधाम से निकाली जाएगी। विगत वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तुर्राधाम जनकल्याण समिति द्वारा आयोजन की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष भगवान भोलेनाथ की बारात को और अधिक भव्य व आकर्षक बनाने के लिए विशेष झांकियों की व्यवस्था की जा रही है। बारात में भूत-पिशाच, नंदी शिव भक्त सहित अनेक धार्मिक एवं पौराणिक झांकियां शामिल रहेंगी, जिससे श्रद्धालुओं में विशेष उत्सुकता बनी रहेगी। 41 वर्षों से जारी परंपरा, अखंड मानस व विशाल मेले का आयोजन रामनगर स्थित तुर्राधाम में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, हनुमान जी महाराज एवं शनिदेव के साथ विराजमान हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस पावन स्थल पर विगत 41 वर्षों से लगातार 24 घंटे का अखंड मानस पाठ एवं भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष आयोजन के मुख्य अतिथि दिलीप जायसवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मध्यप्रदेश शासन होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मनोज विश्नोई (क्षेत्रीय महाप्रबंधक हसदेव क्षेत्र), धर्मेंद्र रघुवंशी राजनगर (उप क्षेत्रीय प्रबंधक ओसीएम राजनगर) एवं एस.के. महतो (उप क्षेत्रीय प्रबंधक राजनगर) श्रीमती रीनू सुरेश कोल अध्यक्ष नगर परिषद डोला श्रीमती ललिता राम यादव अध्यक्ष नगर परिषद खोगापानी कि गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएगे।भगवान भोलेनाथ की बारात न्यू डोला स्थित आधाराम वैश्य के निवास के समीप स्थित शिव मंदिर प्रांगण से बैंड-बाजों के साथ प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए तुर्राधाम पहुंचेगी। नगरवासी सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर पुष्पवर्षा व भक्ति संगीत के साथ बारात का स्वागत करेंगे। बारात में शामिल श्रद्धालु झूमते नाचते भगवान भोलेनाथ की जयघोष करते हुए तुर्राधाम पहुंचेंगे, जहां समिति द्वारा बारातियों के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। 15 फ़रवरी को अखंड मानस 16 फ़रवरी को महाभंडारा व कन्या भोज महाशिवरात्रि पर्व पर 15 फ़रवरी (रविवार) को सुबह 9 बजे से अखंड मानस पाठ प्रारंभ होगा। 16 फ़रवरी (सोमवार) को पूर्णाहुति के पश्चात विशाल महाभंडारे, महिला मंडली द्वारा शिव चर्चा एवं कम से कम 101 कन्याओं के कन्या भोज का आयोजन किया जाएगा। तुर्राधाम जनकल्याण समिति एवं नगर परिषद डोला की ओर से नगर एवं आसपास क्षेत्र के श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं पुण्य लाभ अर्जित करें। तुर्रा धाम जनकल्याण समिति के समस्त पदाधिकारी व सदस्य के साथ नगर परिषद डोला के समस्त नगर वासी श्रद्धालु जन के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल किया जाता है।

पटवारी के पास उपलब्ध नहीं जमीन का नक्शा

उमरिया। जिला अंतर्गत ग्राम नरवार तहसील करकेली पटवारी हल्का घुलघुली का पदस्थ पटवारी के पास आज भी नक्शा उपलब्ध नही है । ग्राम नरवार अंतर्गत लगभग 600हे0 जमीन है । आये दिन जमीनों की खरीद बिक्री भी हो रही है । पूरी खरीद बिक्री सिर्फ कब्जे के आधार पर बेची और खरीदी जा रही है । जिसके चलते आये दिन ग्राम नरवार में विवाद कि स्थिति बनीं रहती है । 2010 की बात करें तो एक व्यक्ति व्दारा पांच एकड जमीन खरीदी गई आज लगभग 8 एकड पर कब्जा बना हुआ है । अगल बगल की जमीनों पर कब्जा होने के चलते लोग परेशान होकर प्रशासन के चक्कर काट रहे है। प्रशासन भी अपना पल्ला झाडते हुए साफ तौर पर कह देता है कि ग्राम नरवार का नक्शा ही उपलब्ध नही है तो जमीनों का सीमांकन व नपाई किस आधार पर की जाए । यह प्रशासन का जवाब कुछ गले से नही उतर रहा है । पटवारी हल्का ज्ञानचंद से जब इस विषय पर बात की गई तो उन्होने बताया कि ग्राम नरवार जो कि लगभग 600हे0 जमीन है उसका पूरे का नक्शा न तो हमारे पास है न ही उमरिया के अभिलेखागार में है , न ही शहडोल के अभिलेखागार में । अब सवाल यह उठता है आखिर ग्राम नरवार का नक्शा कहां गया । यह शासन और प्रशासन दोनो के लिए चुनौती बन चुका है ।

श्री संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा समापन के बाद किया गया विशाल भंडारे का आयोजन

उमरिया । जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत नरवार 29 में

सार्वजनिक नवयुवक समिति द्वारा आयोजित सात दिवसीय संगीत मय श्रीमद्भभागवत कथा का बुधवार को विधि विधान से समापन हो गया। समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी सं या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कथा के समापन के पूर्व बुधवार को सुबह हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रों उ' चारण के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया गया, इसके बाद दोपहर में विशाल भंडारी का शुभारंभ हुआ, भंडारी का शुरुआत में गांव के कन्याओं को प्रसाद ग्रहण कराया गया, इसके उपरांत उन्हें दक्षिणा भी दिया गया, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोग और दूर - दराज से आए श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारी मिश्र धातु प्रसाद छका और पूरे पंडाल में भक्ति से ओत-प्रोत माहौल बना रहा, इस दौरान भक्ति गीतों और जयकारों से वातावरण भक्ति मय हो गया, श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए भक्ति में ली नजर आए, आयोजन की सफ्ल बनाने में ग्राम वासियों का सराहनीय सहयोग रहा। आयोजितकों ने बताया कि सात दिनों तक चली श्री संगीतमय में श्रीमद् भागवत कथा में प्रतिदिन बड़ी सं या में श्रद्धालु शामिल हुए और धर्म का लाभ प्राप्त किया।

चार श्रम कानून के विरोध में संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रव्यापी हड़ताल

एसईसीएल की 12 खदानों के उत्पादन और कोल डिस्पैच का काम ठप,हड़ताल रोकने कॉलरी प्रबंधन की रणनीति फेल

आशा - उषा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मांगों में उतरी सड़कों पर, सौंपा ज्ञापन

विजय मत, अनूपपुर

आगामी दिनों लेबर कोड बिल के लागू होने की संभावनाओं में गुरुवार को अनूपपुर जिले में श्रम संगठनों की संयुक्त मोर्चा की एकदिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है। जिसमें चार श्रम कानून के वापस लेने की मांग पर एटक, एचएमएस, इटंक और सीटू श्रम संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता कोयला खदानों के प्रवेश द्वार पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस राष्ट्रव्यापी एकदिवसीय हड़ताल में बीएमएस ने हड़ताल से दूरी बनाई है। हड़ताल को सफल बनाने सुबह से ही हड़ताल में शामिल श्रम संगठन कोयला खदानों के काम से दूरी बनाते हुए हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही काम पर आने वाले मजदूरों को भी काम का बहिष्कार करवाते खदान से दूर रखे हुए है। मजदूरों के हड़ताल पर जाने से अनूपपुर में एसईसीएल की जमुना कोतमा मुख्य क्षेत्र के साथ हसदेव उपक्षेत्र की लगभग 12 कोयला खदानें प्रभावित हुई है। मजदूरों के अभाव में ना तो कोयला का उत्पादन हो सका है और नहीं परिवहन किया जा सका है। आंकड़ों में देखा जाए तो अनूपपुर जिले में संचालित 18 कोयला खदानों में वर्तमान में 12 ही कोयला उत्पादन का काम कर रहे हैं। इनमें जमुना कोतमा क्षेत्र की दो और हसदेव उपक्षेत्र की लगभग 10 कोयला खदानें शामिल हैं। इनमें हसदेव उपक्षेत्र में रोजाना लगभग 8164.02 टन कोयला उत्पादन होता है। श्रम संगठनों की संयुक्त मोर्चा के अनुसार चार लेबर बिल अंतर्गत श्रमिक संगठनों को हड़ताल से पहले एएलसी को ज्ञापन देकर जानकारी देना होगा, जब तक एसिस्टेंट लेबर कमिश्नर के यहां सुनवाई चलेगी तब तक श्रमिक संगठनों द्वारा हड़ताल नहीं किया जा सकता। अगर इस दौरान हड़ताल किया जाता है तो जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान होगा, कंपनियों द्वारा आवश्यकतानुसार विभिन्न कामों पर जबतक आवश्यकता होगी तबतक कामों रखा

जाएगा जब जरुरत खत्म हो जाएगी श्रमिक को काम से हटा दिया जाएगा, श्रमिक संगठनों को अद्योगिक वार्ता में हिस्सा लेने के लिए 51 फीसदी मेंबरशिप आवश्यक होगी, जिसके पास मेंबरशिप इससे कम होगी उक्त श्रमिक संगठन में से जिस भी श्रमिक संगठन के पास 51 फीसदी मेंबरशिप होगी प्रबंधन उक्त श्रमिक संगठन से वर्ष कमेटी बनाकर अद्योगिक वार्ता करेगी।

हालांकि 12 फरवरी को श्रम संगठनों की प्रस्तावित एक दिवसीय हड़ताल को देखते हुए उप क्षेत्रीय प्रबंधक कुरजा, बिजुरी, बहेराबांध ने कुरजा उप क्षेत्रीय कार्यालय में पांचों श्रमिक संगठनों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाते हुए हड़ताल न करने का किया अनुरोध जेसीसी सदस्यों से किया। लेकिन सदस्यों ने मनाही कर दी। परिणाम बुधवार को बीपीएम के कामगारों की उपस्थिति 536 थी जो गुरुवार की प्रथम पाली में उपस्थिति मात्र 43 मैन पावर रही है।

आशा - उषा और आंगबाड़ी कार्यकर्ता भी उतरी सड़क पर

केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के विरोध में गुरुवार को आशा - उषा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी आवाज बुलंद करते जिला मुख्यालय अनूपपुर के रेलवे अंडरब्रिज के पास धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते कार्यकर्ताओं के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। तीनों संगठनों की कई सैकड़ा कार्यकर्ताओं ने श्रम संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा पूरे देश सहित प्रदेश में भी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की %रीढ़% कही जाने वाली महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय फेडरेशन और सीटू के आह्वान पर आयोजित इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में आशा-उषा कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कर्मी और मध्यान्ह भोजन रसोइयों ने काम बंद किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि %पोषण ट्रैकर% और %संपर्क% जैसे दो-दो एप्स ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एक ही जानकारी दो जगह दर्ज करनी पड़ती है, जिससे समय दोगुना लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क न मिलने के कारण कई बार उन्हें ऊंची पहाड़ियों या छतों पर चढ़कर काम करना पड़ता है। इसके बावजूद तकनीकी खराबी से काम दर्ज न होने पर मानदेय काट लिया जाता है, जिसे उन्होंने सरासर अन्याय बताया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के श्रम सुधारों को श्रमिक विरोधी करार देते हुए इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की। जिनम सभी योजना कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और उचित वेतन, मध्यान्ह भोजन रसोइयों को 10 के बजाय 12 महीने का मानदेय और सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता व 5 हजार रुपए पेंशन, रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 4,000 रुपए, ?संपर्क एप को तत्काल बंद कर मानदेय को एप से जोड़ने की प्रक्रिया खत्म हो। वहीं आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं का कहना था कि हड़ताल के कारण कई टीकाकरण केंद्र, प्रसव सहायता केंद्र और स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था प्रभावित रही। रेखा कुशवाहा व अन्य यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इन %काली संहिताओं% को वापस नहीं लिया और मानदेय संबंधी समस्याओं का निराकरण नहीं किया, तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा।

हाथी ने आहार की खोज में ढाह दी घर की दीवार, मलबे में दबने से वृद्ध घायल, अस्पताल में भर्ती

घायल को वन विभाग की ओर से मिली सहायता राशि, हाथी की निगरानी में अमला मुस्तैद

विजय मत, अनूपपुर

खांडा गांव के ग्रामीणों में दहशत

जिला मुख्यालय अनूपपुर से तीन किलोमीटर दूर ग्राम बरबसपुर में गुरुवार की अहले सुबह एकल दंतैल हाथी ने आहार की खोज में ग्रामीण के कच्चे घर की दीवार ढाह दीए जिसके मलबे के नीचे दबने से 70 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को आनन.फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया हैए जहां वृद्ध का इलाज जारी है। ?घटना की सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वर्ण गौरव सिंह के निर्देश पर वनरक्षक रईस खान और वन्यजीव संरक्षक शशिधर अग्रवाल अस्पताल पहुंचे और घायल वृद्ध को उपचार के लिए प्रारंभिक सहायता राशि उपलब्ध कराई। हाथी से वृद्ध के घायल होने की सूचना पर वन विभाग अमला आसपास के गांव में मुनादी करवाते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बताया जाता है कि बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात एक दंतैल हाथी ने जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बरबसपुर में भारी तबाही मचाई। इस दौरान कई घरों को क्षति भी पहुंचाया और फ्सलों को आहार बनाते अहले सुबह एक आदिवासी परिवार के घर की दीवार ढहा दी। ?जानकारी के अनुसारए हाथी देर रात बरबसपुर के वार्ड क्रमांक 5 ;कपिलधारा कॉलोनी के पीछेद्ध स्थित विशाल भैना ;70 वर्षद्ध के घर पहुंचा। विशाल जमीन पर सो रहे थेए तभी हाथी ने घर की दीवार तोड़ दी। मलबे की चपेट में आने से वृद्ध वहीं दब गए। परिजनों ने साहस दिखाते हुए उन्हें बाहर निकाला। इस दौरान करीब आधे घंटे तक हाथी वहीं डटा रहा और घर में रखी धान की बोरियां फ्ड़कर अनाज चट कर गया। ?ग्रामीणों के शोर मचाने पर हाथी नारायण सिंह के खेत में जा घुसा और गेहूं की फ्सल को नुकसान पहुंचाया इसके बाद वह रामसहाय कोल के घर की दीवार तो?ते हुए रामप्रसाद पाठक के टमाटर और गेहूं के खेतों को रौंदता रहा। गुरुवार को हाथी राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर पोंड़ी और खांडा के बीच सिद्धबाबा पहाड़ी के जंगल में जाकर ठहर गया है। फ्लिहाल ग्रामीण दहशत में हैं और रतजगा करने को मजबूर हैं। ?वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी है। जिले में पिछले डे? माह से हाथियों का दल लगातार संपत्ति और फ्सलों को नुकसान पहुंचा रहा है।

रेलवे मजदूर कांग्रेस की 39 वीं कार्यकारणी सभा सम्पन्न

विजय मत, अनूपपुर

साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर की 39 वीं वर्किंग कमिटी मीटिंग 11 व 12 फरवरी को जोनल कार्यालय बुधवारी बाजार में मुख्य अतिथि जोनल महामंत्री पीतांबर लक्ष्मी नारायण व कार्यक्रम की अध्यक्षता जोनल अध्यक्ष डीके स्वाइन की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के जोनल कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण राव ने बताया कि मजदूर कांग्रेस की हर तीन महीने में वर्किंग कमिटी मीटिंग आयोजित कर संगठन की गतिविधियों की समीक्षा कर अगली रणनीति व रेल कर्मचारियों के हितों के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है।कार्यकारणी सभा को संबोधित करते रेलवे मजदूर कांग्रेस के महामंत्री पीतांबर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि रेलवे मजदूर मजदूर कांग्रेस को नया रुप दे दिया गया है , मजदूर कांग्रेस का हर पदाधिकारी रेल कर्मचारियों के लिए समर्पित है अब रेल मजदूर कांग्रेस, रेल कर्मचारी के द्वारा द्वारा जा कर समस्या सुनेगा, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर रेल मंडल के रेल कर्मचारियों का सभी आभार व्यक्त करते है। मजदूर कांग्रेस के नवीन मेंबरशिप में 16 हजार रेल कर्मचारी 2025 में मेंबर बने 2026 में मजदूर कांग्रेस बिलासपुर 25 हजार मेंबर बनाने का लक्ष्य है। बैठक में जोनल अध्यक्ष डीके स्वाइन ने 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है जिसमें केन्द्रीय कर्मचारियों का 08 वां पे कमीशन को 01 जनवरी 2026 से तत्काल लागू करने की मांग है , ओल्ड पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए।

जिला स्तर पर जिला गणना समन्वय समिति की बैठक 18 फरवरी को

उमरिया। जनगणना 2027 के कार्य एवं गतिविधियों के सुचारू एवं सफ्ल संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तर पर जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक का आयोजन 18 फ्रवरी को समय 4 बजे नियत किया गया है। जनगणना 2027 कार्य हेतु आशीष कुमार श्रीवास्तव एवं अजय सिंह जनगणना निदेशालय भोपाल को प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है।

जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बेठक 16 फरवरी को

उमरिया । खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण की रोकथाम, नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है । जिले में खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम , नियंत्रण हेतु 16 फ्रवरी को समय सीमा की बैठक पश्चात दोपहर 12 बजे से कलेक्टर सभागार में आहूत की गई है ।

चचाई-विवेक नगर मार्ग पर खड़े पेड़ बने जानलेवा खतरा

विजय मत, अनूपपुर

चचाई-विवेक नगर मार्ग पर बीच सड़क में स्थित दो बड़े पेड़ों के कारण लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर नगर परिषद बरगवां (अमलाई) की अध्यक्ष श्रीमती गीता गुप्ता ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इस संबंध में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (स्क्क्रष्टष्ट) के संभागीय प्रबंधक, शहडोल को पत्र लिखकर तत्काल पेड़ों की कटाई, सड़क को सुरक्षित व सुगम बनाने तथा आवश्यक चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की है।अपने पत्र में अध्यक्ष गीता गुप्ता ने उल्लेख किया है कि उक्त मार्ग पर सड़क के बीच खड़े दोनों पेड़ों के कारण वाहन चालकों की दृश्यता बाधित होती है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद न तो वहां कोई चेतावनी संकेतक लगाए गए हैं और न ही बेरिकेडिंग की कोई व्यवस्था की

गई है। इसी लापरवाही के चलते पूर्व में कई बार गंभीर और जानलेवा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।नगर परिषद अध्यक्ष ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि चचाई-विवेक नगर मार्ग पर बीच सड़क में स्थित दोनों पेड़ों को शीघ्र हटाकर मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित हाईवे के रूप में विकसित किया जाए। साथ ही उन्होंने सड़क पर सभी महत्वपूर्ण चेतावनी संकेतक, संकेत बोर्ड एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की भी मांग की है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

कार्यालय नगर परिषद बरगवां (अमलाई)
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)
श्रीमती गीता गुप्ता
अध्यक्ष
नगर परिषद, बरगवां (अमलाई)
मो.- 9584610895, 9098000888
MPRDC संभाग शहडोल
विषय:- चचाई विवेक नगर मार्ग स्थित दोनो पेड़ो की कटाई,सुरक्षित और सुगम हाईवे बनाने एवं महत्वपूर्ण चेतावनी संकेतक की व्यवस्था कराये जानें के संबंध में।
महोदय,
विषयांतर्गत संबंध में लेख है कि चचाई विवेक नगर मार्ग में बीच सडक पर स्थित दो पेडो के कारण आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, इन पेडो की वजह से दृश्यता बाधित होती है जिससे वाहन चालकों को परेशानी बनी रहती है एवं दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। महोदय इस मार्ग पर ना तो चेतावनी संकेतक लगाये गये हैं और ना ही बैरीकेडिंग जिस वजह से पूर्व में कई बार जानलेवा दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं।
अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि चचाई विवेक नगर मार्ग में बीच सडक पर स्थित दोनो पेडों को काट कर सुरक्षित और सुगम हाईवे बनवाने का कष्ट करें और साथ ही सभी महत्वपूर्ण चेतावनी संकेतक सडक पर लगवाने की कृपा करें जिससे भविष्य में पुनः कोई अप्रिय एवं जानलेवा दुर्घटनाएँ ना हो।
अध्यक्ष
नगर परिषद बरगवाँ(अमलाई)
जिला–अनूपपुर(म.प्र.)
प्रतिलिपि–
1. श्रीमान मुख्य महाप्रबंधक महोदय MPRDC भोपाल(म0प्र0)कि ओर सूचनार्थ।
2. श्रीमान मुख्य अभियंता MPRDC अनूपपुर(म0प्र0) कि ओर सूचनार्थ।
अध्यक्ष
नगर परिषद बरगवाँ(अमलाई)
जिला–अनूपपुर(म.प्र.)

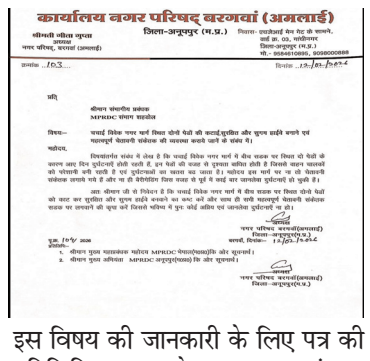

इस विषय की जानकारी के लिए पत्र की प्रतिलिपि स्क्क्रष्टष्ट के मुख्य महाप्रबंधक, भोपाल तथा मुख्य अभियंता, अनूपपुर को भी प्रेषित की गई है।स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद अध्यक्ष की इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि संबंधित विभाग शीघ्र कार्रवाई कर इस मार्ग को दुर्घटनामुक्त बनाएगा।

मांग

डॉ. सुनील चौरसिया ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, बजट में पृथक शीर्ष बनाने का आग्रह

कोयलांचल के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग

विजय मत, अनूपपुर

मध्यप्रदेश विधानसभा में 16 फरवरी से प्रारंभ होकर 18 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले राज्य बजट से पहले अनूपपुर जिले के कोयलांचल क्षेत्र के विकास को लेकर अहम पहल की गई है। जिला योजना समिति के सदस्य एवं नगर परिषद डूमरकछार के अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार चौरसिया ने मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री को पत्र लिखकर कोयलांचल क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु बजट में विशेष पैकेज घोषित करने की मांग की है। डॉ. चौरसिया ने पत्र में उल्लेख किया है कि जमुना कोतमा, बिजुरी, रामनगर, राजनगर कालरी, डूमरकछार, आमाडांड, डोला सहित आसपास का पूरा क्षेत्र देश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में शामिल रहा है। दशकों तक प्रदेश और राष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाला यह क्षेत्र आज बुनियादी सुविधाओं के अभाव, बेरोजगारी, पलायन, पर्यावरणीय संकट और अव्यवस्थित पुनर्वास जैसी समस्याओं से जूझ रहा है।

बेरोजगारी और पलायन पर चिंता

पत्र में कहा गया है कि कोयला खदानों के बंद होने के बाद क्षेत्र में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। डॉ. चौरसिया ने मांग की है कि बंद खदानों की शेष उपयोगी भूमि पर उद्योग-धंधों और कल-कारखानों की स्थापना की जाए, ताकि सेवानिवृत्त श्रमिकों, उनके आश्रितों और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके।

खाली पड़े आवासों का उपयोग

कोल इंडिया के हजारों खाली पड़े आवासीय मकानों का जिक्र करते हुए उन्होंने सुझाव दिया

है कि राज्य सरकार इन्हें अपने अधिपत्य में लेकर आंशिक सुधार के बाद मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद हितग्राहियों को आवंटित करे। इससे जहां जरूरतमंदों को आवास मिलेगा, वहीं खाली परिसरों का सदुपयोग भी हो सकेगा।

पुनर्वास योजना और प्राधिकरण गठन की मांग

डॉ.चौरसिया ने वर्तमान पुनर्वास योजनाओं को अप्रभावी बताते हुए उन्हें और प्रभावी बनाने की आवश्यकता जताई है। साथ ही ÷कोयलांचल क्षेत्र पुनर्विकास प्राधिकरण (ष्टश्ड्डद्यद्बद्दद्यस्र् हद्गड्ड ष्ठद्ग1द्गद्यश्चद्वद्गठ्ठह्ल ह्रह्वह्लद्धश्रह्म्द्बह्ल4)÷ के गठन की मांग की है, जो बंद और चालू खदान क्षेत्रों के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार करे।

हरित विकास और पर्यटन को बढ़ावा

उन्होंने बंद खदान क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण, जलाशय निर्माण एवं पर्यटन विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं। इसके अलावा लघु उद्योग एवं स्स्स्ध क्लस्टर स्थापित करने की भी मांग की गई है।

सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय का प्रश्न

डॉ. चौरसिया ने इसे केवल क्षेत्रीय विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक एवं पर्यावरणीय न्याय से जुड़ा विषय बताया है। उन्होंने आगामी बजट में इन सभी मांगों के लिए पृथक शीर्ष (स्श्चद्गष्द्बड्ढ्य क्चह्वस्रद्दद्गह्ल ॥द्गड्डस्र) बनाकर विशेष पैकेज घोषित करने तथा उच्च स्तरीय सर्वे समिति गठित कर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने का आग्रह किया है।

उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की सकारात्मक पहल से कोयलांचल क्षेत्र के लाखों नागरिकों के जीवन स्तर में ऐतिहासिक और स्थायी सुधार संभव होगा।

न्यूज इन शॉर्ट

प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में काँग्रेस की जन आक्रोश रैली

शहडोल। मध्यप्रदेश काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी की विशेष उपस्थिति एवं जिला काँग्रेस कमेटी शहडोल के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, शहडोल जिले की ज्वलंत जनसमस्याओं को लेकर दिनांक 13 फरवरी 2026, शुक्रवार को काँग्रेस द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जन आक्रोश रैली शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय युवाओं को रोजगार, किसानों की मूलभूत समस्याओं, अवैध रेत उत्खनन तथा शासन-प्रशासन की तानाशाहीपूर्ण कार्यप्रणाली के विरोध में आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दोपहर 02 बजे अंबेडकर चौक पहुंचेंगे, जहाँ से जन आक्रोश रैली प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौक में समाप्त होगी। रैली के समापन पर विशाल आमसभा आयोजित की जाएगी, जिसके उपरांत प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जनहित से जुड़ी मांगें रखी जाएंगी। इसके पश्चात माननीय प्रदेश अध्यक्ष वार्ड कमेटियों के संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने समस्त काँग्रेसजनों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस जनहितार्थ जन आक्रोश रैली को सफल बनाएं।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

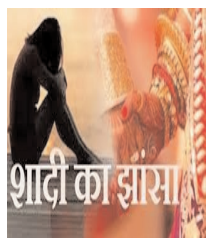

शहडोल। विवाहित महिला द्वारा थाना सिंहपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वर्ष 2022 में उसकी जान.पहचान ग्राम केलमनिया निवासी रामसुफल बैगा से हुई थी। आरोपी द्वारा उसे पति को छोड़कर विवाह करने का प्रलोभन दिया गया तथा शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किए गए। बाद में आरोपी द्वारा विवाह करने से इंकार कर दिया गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना सिंहपुर में आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना सिंहपुर पुलिस द्वारा आरोपी की सतत् तलाश की गई। परिणामस्वरूप आरोपी रामसुफल बैगा निवासी ग्राम केलमनिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिंहपुर निरीक्षक एमएल राहंगडाले के नेतृत्व में विवेचक उप निरीक्षक आशीष झारिया आरक्षक आलोक सिंह एवं आरक्षक हीरालाल महरा की सराहनीय भूमिका रही।

अवैध कोयला भंडारण पर बुढार पुलिस की कार्यवाही 10 क्विंटल कोयला जप्त एक आरोपी गिरफ्तार

शहडोल। थाना बुढार पुलिस द्वारा अवैध खनिज के विरुद्ध

कार्यवाही करते हुए ग्राम मरजाद स्थित एक ईंट भट्टे से अवैध कोयला जप्त कर 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

कस्बा भ्रमण के दौरान बुढ़ार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दुर्गेश प्रजापति एवं रवि प्रजापति के ईंट भट्टा ग्राम मरजाद में बिक्री करने हेतु अवैध कोयला भंडारित है। सूचना पर बुढ़ार पुलिस दल द्वारा मौके पर पहुंचकर रेड कार्यवाही की गईए जहां आरोपी रवि प्रजापति पिता लालू प्रजापति उम्र 26 वर्षए निवासी वार्ड नं. 09ए धनपुरी नं. 03 थाना अमलाईए जिला शहडोल को अवैध कोयले के साथ पकड़ा गया।आरोपी से लगभग 10 क्विंटल काला कोयला कीमत लगभग 7000. रुपये विधिवत जप्त किया गया। पुलिस द्वाना उक्त कोयले के संबंध में कोई वैध दस्तावेज मांगने पर आरोपी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी के विरुद्ध बीएनएस एवं खान एवं खनिज ;विकास एवं विनियमनद्ध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में सह.आरोपी दुर्गेश प्रजापति की तलाश जारी है।

कोल माफियाओं ने दी वन कर्मियों को गोली मारने की धमकी

विजय मत, शहडोल

दक्षिण वनमंडल शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़खेरा खितौली बीट सीमा में अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई कर लौट रही वन विभाग की टीम पर संगठित हमला किए जाने और गोली मार देने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर वन विभाग की ओर से थाना सोहागपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है,जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

आवेदन में मारपीट और पथराव का आरोप

वन परिक्षेत्राधिकारी सोहागपुर रामनरेश विश्वकर्मा द्वारा दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि 11 फरवरी 2026 को टीम सोन नदी क्षेत्र में अवैध उत्खनन की सूचना पर जांच के लिए पहुंची थी। कार्रवाई कर लौटते समय बड़खेरा निवासी चेतन सिंह एवं अन्य लोगों ने रास्ता रोक लिया। आवेदन के अनुसार 20-25 लोगों की भीड़ ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और वन विभाग के वाहन पर पथराव किया। स्थिति बिगड़ने पर टीम को वहां से जान बचाकर सुरक्षित निकलना पड़ा।

घटना को लेकर अलग-अलग दावे भी सामने आए

घटना के बाद गांव में अलग-अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उस समय गांव में शादी का कार्यक्रम चल रहा था और वन विभाग की हूटर बजाती गाड़ियां पहुंचने से माहौल बिगड़ गया। हूटर बंद कराने को लेकर विवाद की स्थिति बनी, जो बाद में बढ़ गई। वहीं यह भी चर्चा में है कि जिस स्थान पर कार्रवाई की गई, वह राजस्व क्षेत्र बताया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि यदि अवैध उत्खनन राजस्व भूमि पर हो रहा था तो वहां वन अमले की कार्रवाई किस आधार पर की जा रही थी। यह पहलू अब जांच और प्रशासनिक स्पष्टता की मांग कर रहा है।

डॉग स्क्वाड के साथ गश्ती टीम पर हाथापाई

गश्ती के दौरान डॉग स्क्वॉड के साथ श्यामडीह-बड़खेरा होते हुए पटासी की ओर जा रही टीम को बड़खेरा के पास बेटन सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह, चिंटू सिंह, महेश सिंह सहित 30-40 लोगों ने रोक लिया। वन विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया कि भीड़ ने गाली-गलौज, अभद्रता की, वनमंडलाधिकारी के नाम से अपशब्द कहे, टीम को वाहन से खींचकर हाथापाई की और दोबारा क्षेत्र में दिखने पर गोली मारने की धमकी दी।

पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल

इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि संबंधित क्षेत्र राजस्व भूमि है और वहां लंबे समय से अवैध कोयला उत्खनन जारी था, तो फिर पुलिस की भूमिका पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। ग्रामीणों का दावा है कि पूर्व में भी सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध कोयले का कारोबार लगातार चलता रहा है। नवागत थाना प्रभारी के पदभार ग्रहण करने के बाद भी इस पर प्रभावी रोकथाम नहीं हो सकी है। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार पहले अवैध गतिविधियां संचालित होती थीं, वैसी ही स्थिति अब भी बनी हुई है। ऐसे में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।

डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे का सख्त रुख

दक्षिण वनमंडल की डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे ने बयान में स्पष्ट किया कि वन क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन और परिवहन के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वन भूमि पर अवैध गतिविधि किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।वन अमले पर हमला गंभीर अपराध है।दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।विभाग लगातार गश्ती बढ़ाकर निगरानी मजबूत कर रहा है।डीएफओ ने कहा कि अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।मामले को लेकर पुलिस जांच प्रारंभ कर चुकी है।अब यह देखना होगा कि जांच में हमले की पुष्टि किस हद तक होती है और राजस्व-वन सीमा विवाद का पहलू किस दिशा में जाता है।

इनका कहना है।

सोहागपुर थाना प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि विभाग द्वारा सुबह कथन प्रस्तुत नहीं किया गया था। शाम को संबंधित अधिकारी थाने पहुंचकर कथन दर्ज करा रहे हैं। कथन के आधार पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अवैध खनन व परिवहन पर सख्त कार्रवाई, दो डम्पर जब्त

शहडोल। कलेक्टर शहडोल के निर्देशन में खनिज विभाग द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2026 को अवैध खनन एवं खनिज परिवहन के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दो डम्परों को जब्त किया गया। जांच के दौरान ग्राम कंचनपुर के पास गिट्टी खनिज का अवैध परिवहन करते हुए डम्पर क्रमांक MP18 GA 1824 को रोका गया। वाहन चालक बबलू बैगा, निवासी जमुई द्वारा मौके पर वैध रॉयल्टी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके पश्चात वाहन को शासकीय अभिरक्षा में खड़ा कराते हुए चालक एवं वाहन मालिक के विरुद्ध अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।इसी क्रम में खनिज अमले द्वारा डम्पर क्रमांक MP18 ZF 0497 को रेत खनिज के परिवहन के दौरान रोका गया। चालक द्वारा रेत परिवहन की ॅज्ञ्ज्क्कप्रस्तुत की गई, किंतु जांच में वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक खनिज भरा पाया गया। इस पर उक्त डम्पर को भी शासकीय अभिरक्षा में लेते हुए चालक एवं वाहन मालिक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। संपूर्ण कार्रवाई खनिज निरीक्षक शहडोल श्री अभिषेक पटले द्वारा खनिज अमले के साथ संयुक्त रूप से की गई।

अवैध रेत परिवहन पर की गई कार्यवाही, ट्रैक्टर-ट्राली जप्त

शहडोल। पुलिस अधीक्षक श्री रामजी श्रीवास्तव के निर्देशन में शहडोल जिले में खनिजो के अवैध उत्खन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना देवलोंद पुलिस को अवैध रेत परिवहन की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर थाना देवलोंद पुलिस द्वारा के थाना प्रभारी उ.नि. सुभाष दुबे के नेतृत्व में सहा.उप.नि. इन्दलाल पुरी, सउनि महेश झा, आर. अभिषेक तिवारी, आर. आदित्य सिंह एवं चालक रजनीश विश्वकर्मा के साथ ग्राम झिरिया मौहार के पास दबिश दी गई। मौके पर एक लाल रंग का बिना नंबर का मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर व ट्राली में आधी ट्राली रेत भरा हुआ पाया गया। मौके पर पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम ददोल बैस पिता मंगलदीन बैस, निवासी ग्राम झिरिया थाना देवलोंद जिला शहडोल (म.प्र.) बताया। रेत परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

चिन्हित कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को एन.आर.सी. में कराएं भर्तीः कलेक्टर

विजय मत, शहडोल

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने जिले के कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की जानकारी लेते हुए आधिकारियों को निर्देश दिए कि शहडोल जिले के कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर एन.आर. सी. केंद्रो में भर्ती कराना सुनिश्चित करें उन्होंने कुपोषण मुक्त अभियान में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नियमित मानीटरिंग करते हुए प्रगति लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि ब्यौहारी तहसील के निपनिया स्वास्थ्य केंद्र एवं बुढार तहसील के झींकबिजुरी में एनआरसी केंद्र संचालित करें एवं कोई भी एनआरसी केंद्र रिक्त न हो यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जाने वाली संदर्भ सेवाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाते है उनका चिन्हांकन करें। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाईरिस्क गर्भवती माताओं को चिन्हित कर उनकी मॉनिटरिंग करें एवं घर-घर जाकर गर्भवती माताओं से स्वास्थ्य संबंधित जानाकारी प्राप्त कर आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सुविधाएं एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं।

कलेक्टर ने आभा आई डी, ए. एन.सी. पंजीयन, पी एम मातृत्व योजना,एसएनसीयू सहित स्वास्थ्य विभाग एव महिला बाल विकास विभाग द्वारा किए जा रहे अन्य कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश आधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डॉ. राजेश मिश्रा, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्री

जन्म मृत्यु पंजीयन एवं विवाह पंजीयन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

विजय मत, शहडोल

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जिले में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश जिले के जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को दिए हैं। जन्म-मृत्यु एवं विवाह का पंजीयन कराना प्रत्येक नागरिक का कानूनी दायित्व है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन निर्धारित समय सीमा के भीतर कराया जाना अनिवार्य है, जिससे नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं, प्रमाण-पत्रों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।

जन्म प्रमाण-पत्र शैक्षणिक प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन, उत्तराधिकार सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज है। वहीं मृत्यु प्रमाण-पत्र संपत्ति हस्तांतरण, बीमा दावा, बैंक संबंधी कार्य एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है। इसी प्रकार विवाह पंजीयन पति-पत्नी के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा एवं विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जन्म, मृत्यु एवं विवाह से संबंधित घटनाओं का पंजीयन निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से संबंधित पंजीयन कार्यालय, नगर निकाय अथवा ग्राम पंचायत में कराएं। निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीयन कराने पर नियमानुसार विलंब शुल्क देय हो सकता है।दीवार लेखन के माध्यम से जन्म पंजीकरण के लिए जन्म आपका हक, पंजीकरण जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का पहला अधिकार सुरक्षित भविष्य की पहली पुकार, जीवन की शुरूआत, पंजीकरण के साथ। इसी तरह मृत्यु पंजीकरण के लिए अंतिम यात्रा का हो सम्मान, मृत्यु का हो सही प्रमाण, जो चले गए उनकी यादें खास, पंजीकरण है परिवार का विश्वास। मृत्यु के बाद भी परिवार का साथ पंजीकरण है कानूनी बात।

जिला अस्पताल में इलाज के साथ ठहरने की त्रासदी, धर्मशाला बदहाली की शिकार

राहुल मिश्रा, विजय मत, शहडोल

जिला अस्पताल, जो पूरे संभाग के हजारों गरीब और ग्रामीण मरीजों के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र है, वहीं अब परिजनों के लिए परेशानी का पर्याय बनता जा रहा है। दूर-दराज़ गांवों से अपनों का इलाज कराने पहुंचे परिवारों को न सिर्फ बीमारी से जूझना पड़ रहा है, बल्कि सिर छिपाने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढना भी बड़ी चुनौती बन गया है। अस्पताल परिसर में बनी धर्मशाला बदहाल पड़ी है, जिसके चलते परिजन वार्डों के बाहर, गलियारों में या खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं।

अस्पताल प्रबंधन के दावों में धर्मशाला की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कई परिजन अस्पताल के बरामदों और सीढ़ियों के पास चादर बिछाकर रात काटते नजर आते हैं। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। इलाज की चिंता के बीच ठहरने की असुरक्षा उन्हें मानसिक रूप से भी थका रही है।

साल 2004 में एक समाजसेवी ट्रस्ट द्वारा लाखों रुपये की लागत से निर्मित धर्मशाला आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। परिसर में गंदगी का अंबार, टूटी खिड़कियां और बदबूदार कमरे इसकी स्थिति बयान करते हैं। नियमित साफ-सफाई और रखरखाव के अभाव में यह भवन उपयोग के लायक नहीं रह गया है। जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था, वह उद्देश्य अधूरा दिखाई दे रहा है।

रात ढलते ही धर्मशाला परिसर में अंधेरा छा जाता है। पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति से यहां असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायतें सामने आती रही हैं। सुंती बैगा जैसी महिलाओं ने बताया कि पूर्व में लूटपाट की घटनाओं के कारण यहां रुकना असुरक्षित महसूस होता है। ऐसे में कई परिजन मजबूरी में खुले स्थानों पर ही रुकना बेहतर समझते हैं।ठंड, गर्मी या बारिश, हर मौसम में परिजन अस्पताल परिसर के बाहर ही चूल्हा जलाकर भोजन बनाते और जमीन पर सोते दिखाई देते हैं।

कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रमुख दायित्वः कमिश्नर

शहडोल। आयुक्त शहडोल संभाग श्रीमती सुरभि गुप्ता ने संभाग के तीनों जिलों के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुपोषण से मुक्ति विभाग की प्राथमिक जिम्मेवारी है। विभागीय अधिकारी निरंतर भ्रमण कर आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें की सभी आंगनवाड़ी केन्द्र समय पर संचालित हों, केन्द्रों में प्री स्कूल गतिविधियां संचालित की जाएं। जिसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाए। निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों के सुधार के साथ ही संबंधित अमले के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती मनीषा लुम्बा, जिला कार्यक्रम अधिकारी शहडोल श्री अखिलेश मिश्रा, अनूपपुर श्री विनोद परस्ते, उमरिया श्रीमती दिव्या गुप्ता, सहायक संचालक राकेश खरे तथा तीनों जिलों के परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे।आयुक्त ने निर्देश दिए कि नवचिन्हत गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण ट्रेकर एप में दर्ज कराएं। आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों का नियमित वजन एवं लम्बाई की माप कर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करते हुए अनिवार्य रूप से पंजीयन कराया जाए। जो बच्चे कुपोषित श्रेणी में हैं उन्हें एनआरसी में भर्ती कराकर सामान्य पोषण स्तर पर लाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि ये बच्चे पुनः कुपोषण श्रेणी में नहीं जाएं। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर द्वारा नियमित मानीटरिंग तथा समय पर दवाओं का सेवन एवं बच्चों के भोजन की मानीटरिंग सुनिश्चित की जाए। आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को समय पर नास्ता एवं भोजन का वितरण हो। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय-सीमा मे पूरी कर ली जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सीडीपीओ आंगनवाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करें।

आयुक्त ने आभा आईडी, अपार आईडी तथा समग्र सत्यापन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएमजनमन,डीएमएफ तथा विभागीय योजनाओं से बनने वाली आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराएं।

जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छ शौचालय नहीं हैं एवं विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है के कार्य भी फरवरी माह में पूरा कराएं। आंगनवाड़ी केन्द्रों की रंगाई-पुताई एवं मेन्टीनेंश हेतु मिलने वाली राशि का सही उपयोग किया जाए। सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली, पानी, बाउन्ड्रीवाल, किचन गार्डन, एलईडी तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मातृ वंदना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना में शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ सभी पात्र छात्राओं को देना सुनिश्चित किया जाए। विभाग में जिन सेवकों की विभागीय जांच लंबित है शीघ्र जांच पूरी कराई जाए तथा लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

समस्या

उखड़े ढक्कन और खुले गड्ढों से राहगीर परेशान, शिकायतों के बाद भी नहीं हुई मरम्मत

टूटे चैंबर बने खतरा, कन्या महाविद्यालय मार्ग पर बढ़ी चिंता

विजय मत, शहडोल

जिला मुख्यालय स्थित इंदिरा गांधी शासकीय कन्या महाविद्यालय की ओर जाने वाले मार्ग पर टूटे और उखड़े चैंबर गंभीर समस्या का रूप ले चुके हैं। फुटपाथ और सड़क किनारे बने चैंबरों के ढक्कन जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हैं, जिससे पैदल चलना तक जोखिम भरा हो गया है। महाविद्यालय आने-जाने वाली छात्राओं और स्थानीय नागरिकों को रोजाना इन खतरनाक हालात का सामना करना पड़ रहा है।

फुटपाथ पर चलना हुआ मुश्किल

फुटपाथ पर लगे कई चैंबर के ढक्कन या तो पूरी तरह टूट चुके हैं या अपनी जगह से हटे हुए हैं। कुछ स्थानों पर चैंबर खुले पड़े हैं, जो गहरे गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। ऐसे में राहगीरों को मजबूरन सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। विशेषकर शाम के समय या कम रोशनी में इन गड्ढों को देख पाना मुश्किल हो जाता है।

छात्राओं और बुजुर्गों के लिए

बढ़ा खतरा

महाविद्यालय की छात्राएं प्रतिदिन इसी मार्ग से आती-जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले चैंबर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हैं। क्षेत्र के निवासियों ने बताया कि कई बार लोग असंतुलित होकर गिर चुके हैं। हालांकि अब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं।

शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया है। मौखिक शिकायतों के साथ-साथ लिखित आवेदन भी दिए गए, लेकिन अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते चैंबरों की मरम्मत नहीं कराई गई तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

बारिश में और बिगड़ जाती है स्थिति

बरसात के दौरान सड़क और फुटपाथ पर पानी भर जाता है, जिससे खुले चैंबर दिखाई नहीं देते। पानी के नीचे छिपे गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालक फिसलकर गिर जाते हैं। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि इस समस्या से ग्राहक भी परेशान हैं और क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हो रहा है।

क्षतिग्रस्त चैंबरों बदलकर लगाए मजबूत

क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि क्षतिग्रस्त चैंबरों को तत्काल बदलकर मजबूत ढक्कन लगाए जाएं और नियमित निगरानी की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

इटली की टी-20 वर्ल्ड कप में पहली जीत, नेपाल को 10 विकेट से हराया

मुम्बई,एजेंसी

नई दिल्ली, एजेंसी

इटली ने टी-20 वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल की है। टीम ने नेपाल को 10 विकेट से हराया। ग्रुप सी के इस मैच में इटली ने 124 रन का टारगेट 12.4 ओवर में बिना नुकसान के चेज कर दिया। मोस्का ब्रदर्स ने शतकीय साझेदारी की। जस्टिन मोस्का ने नाबाद 60 और एंथोनी मोस्का ने नाबाद 62 रन बनाए।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इटली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। नेपाल 19.3 ओवर में 123 रन पर ऑलआउट हो गई। नेपाल के आरिफ शेख ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए। दीपेंद्र सिंह ऐरी 17 रन, रोहित पौडेल 23 रन और आसिफ शेख 20 रन बनाकर आउट हुए।क्रिशन कालुगामगे ने 3 विकेट झटके। बेन मेनेंटी को 2 विकेट मिला। अली हसन, जेजे स्मट्स और जसप्रीत सिंह को एक-एक विकेट मिला। मैच का स्कोरबोर्ड

नेपाल- कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, लोकेश बम, गुलशन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने और ललित राजबंशी।

इटली: जस्टिन मोस्का, एंथोनी मोस्का, जेजे स्मट्स, हैरी मेनेंटी (कप्तान), बेन मेनेंटी, मार्कस कैंपोपिनो, ग्रांट स्टुअर्ट, जीपी मीडे, जसप्रीत सिंह, क्रिशन कालुगामगे, अली हसन।

एंथोनी मोस्का के बल्ले से निकली इटली की पहली जीत

इटली ने टी-20 वर्ल्ड कप में पहला मैच जीत लिया है। टीम ने नेपाल को 10 विकेट से हराया। इटली ने 124 रन का टारगेट 12.4 ओवर में चेज कर लिया है।

न्यूजीलैंड के फिन एलन सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने

अभिषेक का रिकार्ड तोड़ा

नई दिल्ली । न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने टी20 विश्व कप में यूएई के खिलाफ मुकाबले में अपनी 84 रनों की पारी के दौरान सबसे तेजी से 5000 रन पूरे करने का रिकार्ड अपने नाम किया है। इसी के साथ ही उन्होंने भारत के अभिषेक शर्मा के सबसे तेज 5000 रनों का रिकार्ड तोड़ दिया। इस मैच में कीवी टीम ने बिना कोई विकेट गंवाये ही 173 रन बनाकर मुकाबला जीता। एलन के सलामी जोड़ीदार टिम सीफर्ट ने नाबाद 89 रन बनाये।एलन ने केवल 2854 गेंदों में ही अपने 5000 रन पूरे किए हैं। वहीं अभिषेक ने 2898 गेंदों में ये आंकड़ा हासिल किया था। इस तरह एलन ने अभिषेक से 44 कम गेंदें खेली। सूची में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के धुरंधर आंद्रे रसेल हैं जिन्होंने 2942 गेंदों में 5 हजार टी20 रन बनाये। विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड इस सूची में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने 5 हजार रन 3127 गेंदों में बनाये। पांचवें नंबर पर विल जैक्स हैं जिन्होंने 3196 गेंदों में 5 हजार रन बनाये। आदिल ने ग्रुप-सी के मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 17 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके साथ ही आदिल के वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 41 विकेट हो गये हैं। वहीं, रऊफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 टी20 मैचों में 40 विकेट लिए थे। दूसरे विकेट लेने के साथ ही आदिल ने टी20 क्रिकेट में अपने 400 विकेट भी पूरे कर लिए। वह इंग्लैंड की ओर से ये आंकड़ा हासिल करने वाले केवल दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि केवल क्रिस जॉर्डन के नाम थी।

घुड़सवारी महासंघ पर आयकर का शिकंजा

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 156 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) को पहली बार 4.62 करोड़ रुपये का मांग नोटिस जारी किया है। आधिकारिक दस्तावेजों में यह जानकारी दी गई है।

ईएफआई को नौ फरवरी, 2026 के नोटिस में कहा गया है कि इस खेल महासंघ को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4,62,18,102 रुपये की राशि भुगतान करनी होगी। इस नोटिस की एक प्रति पीटीआई के पास भी है जिसमें कहा गया है कि निर्धारित की गई राशि नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर किसी अधिकृत बैंक में जमा करनी होगी। ईएफआई के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा महासंघ के पदाधिकारियों को लिखे गए पत्र के अनुसार, कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें आयकर विभाग के समक्ष पेश करना जरूरी था।इस मामले के संबंध में एक अंतिम संचय प्रमाण पत्र भी तैयार किया गया है ।

टेनिस प्लेयर फेडरर टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल

मुम्बई,एजेंसी

` रोजर फेडरर ने भले ही टेनिस को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनका जादू अब भी प्रशंसकों पर सर चढ़कर बोलता है जिसकी बानगी यहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के समारोह के टिकटों की भारी मांग में देखने में मिली।इस समारोह के सभी टिकट दो मिनट में बिक गए। आयोजकों ने आउटडोर पार्टी के लिए अलग से अतिरिक्त टिकट जारी किए जो हाथों हाथ बिक गए। आखिर में आयोजकों को कहना पड़ा कि उनकी क्षमता सीमित है और वह अधिक टिकट जारी नहीं कर सकते हैं। आयोजक हॉल ऑफ फेम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक स्थल होने के कारण हमारी क्षमता सीमित है।हॉल ने कहा कि उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी फेडरर को लेकर कितना उत्साह होगा। इस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को 29 अगस्त को प्रसारक मैरी कैरिलो के साथ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा।

मुख्य समारोह के लिए पहले से उपलब्ध 900 टिकटों के अलावा हॉल अपने 3,600 सीटों वाले स्टेडियम को एक विशेष कार्यक्रम के लिए खोलेगा।

आईसीसी ने नबी पर जुर्माना लगाया

अहमदाबाद । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मोहम्मद नबी पर आचार संहित उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाया है। नबी पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच में आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। यह नियम अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के निर्देश को न मानने से जुड़ा है। जुर्माने के अलावा नबी के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक नकारात्मक अंक भी जोड़ा गया है। पिछले 24 महीने में उनकी यह पहली गलती थी।

यह मामला अफगानिस्तान की पारी के 14वें ओवर का है जब नबी की अंपायरों के साथ गेंदबाज लुंगी एनगिडी के कलाई बैंड को लेकर बहस हो गयी। नबी ने अपनी गलती मान ली है ।

माइक टायसन को हराने वाला फाइटर फूट-फूटकर रोया

मिलानो, एजेंसी

कोर्टिना विंटर ओलंपिक 2026 में डच स्पीड स्केटर जुट्टा लीरडैम ने महिलाओं की 1000 मीटर रेस में 1:12.31 का समय निकालते हुए नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। जैसे ही वह फिनिश लाइन पार कर गोल्ड की हकदार बनीं, स्टैंड में बैठे उनके मंगेतर जेक पॉल की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए।

29 वर्षीय बॉक्सर और सोशल मीडिया स्टार अपनी मां पाम और लीरडैम की मां मोनिक के साथ मुकाबला देख रहे थे। सिल्वर (बीजिंग 2022) से गोल्ड तक का सफर पूरा होते ही जेक फूट-फूटकर रोने लगे। यह पल दोनों लंबे समय से देख रहे थे।

लीरडैम के लिए यह सीजन आसान नहीं था। क्वालिफिकेशन के दौरान गिरने के बाद उन्हें चयन के लिए विशेष अनुमति की जरूरत पड़ी थी, लेकिन मिलान पहुंचकर उन्होंने मौका भुना और इतिहास रच दिया। उनकी टीममेट फेम्के कोक ने 1:12.59 के साथ सिल्वर, जबकि जापान की ताकागी मिहो ने ब्रॉन्ज जीता।

जेक पॉल ने रोते हुए अपना वीडियो शेयर किया और लिखा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है जुट्टी लीरडैम। एक और वीडियो में उन्होंने लीरडैम को उठाया और लिखा, हमने खेल इतिहास के सबसे खास पलों में से एक देखा। शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मुझे तुम पर कितना गर्व है।

टायसन को भी दे चुके हैं मात

जेक पॉल वही फाइटर हैं जिन्होंने नवंबर 2024 में महान मुक्केबाज माइक टायसन को प्रोफेशनल फाइटिंग में हराकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन इस बार जीत रिंग में नहीं, दिल में महसूस हो रही थी।

दुनिया के महानतम मुक्केबाजों में शामिल माइक टायसन लगभग दो दशक के बाद नवंबर 2024 में पेशेवर मुकाबले के लिए उतरे। 58 साल के टायसन का सामना पूर्व सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और पेशेवर बॉक्सर जेक पॉल से था। इस मैच को पॉल ने सर्व-सम्मत से जीत लिया, लेकिन टायसन आठ राउंड तक डटे रहे और फैंस का दिल जीता। सबसे बड़ी बात यह रही कि पॉल नॉकआउट मास्टर माने जाते हैं, लेकिन वह टायसन को हिला तक नहीं सके और टायसन आठवें राउंड तक बने रहे। पॉल ने चार अंक से मैच अपने नाम किया। आठ राउंड के बाद पॉल को 78 पॉइंट और टायसन को 74 पॉइंट मिले थे। टायसन को भी दे चुके हैं मात

जेक पॉल वही फाइटर हैं जिन्होंने नवंबर 2024 में महान मुक्केबाज माइक टायसन को प्रोफेशनल फाइटिंग में हराकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन इस बार जीत रिंग में नहीं, दिल में महसूस हो रही थी।

टी20 विश्वकप के बहिष्कार का फैसला सरकार का था : आसिफ

ढ़ाका, एजेंसी

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक बार फिर अपने बयान से पलटते हुए कहा है कि टी20 विश्वकप क्रिकेट के बहिष्कार का फैसला सरकार का था। इससे पहले कल उन्होंने कहा था कि ये फैसला खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) का था। वहीं शुरुआत में कहा था कि सुरक्षा कारणों से टीम भारत नहीं भेजी जा सकती है।

नजरुल ने इस मामले में बुधवार को सफाई देते हुए कबूल किया कि वह इस मुद्दे पर सही तरह से अपनी बात नहीं रख पाये थे। उन्होंने कहा, 'एक बार फिर मैं कहता हूं कि विश्व कप में नहीं खेलने का फैसला सरकार का था।' नजरुल ने कहा कि उनके पिछले बयान को गलत तरीके से लिया गया। बीसीबी के कार्यक्रम में उनसे ये पूछा गया कि क्या विश्व कप में नहीं खेलने का उन्हें कोई पछतावा है, न कि ये पूछा गया कि फैसला किसने लिया था।

नजरुल के अनुसार सरकार ने जनवरी की शुरुआत में ही फैसला कर लिया था कि सुरक्षा चिंताओं की वजह से भारत में टीम नहीं भेजी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी पिछले कई बयानों में ये बात स्पष्ट कर चुके हैं।नजरुल ने ये भी कहा कि बोर्ड और खिलाड़ियों ने बिना कोई विरोध किए सरकार का फैसला स्वीकार किया जो हमारे लिए खुशी की बात है। इसके बाद भी बोर्ड और खिलाड़ियों ने बिना कोई सवाल किए सरकार का फैसला स्वीकार किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और गरिमा के हित में लिए गए फैसले का समर्थन करने के लिए खिलाड़ियों और अधिकारियों की तारीफ की।

व्यापार

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद सेंसेक्स 558 , निफ्टी 146 अंक गिरा

मुंबई,एजेंसी

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट एशियाई बाजारों से मिले सकरात्मक संकेतों के बाद भी आईटी शेयरों में बिकवाली के कारण आई है। इससे दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाबा बीएसई सेंसेक्स 558.72 अंक टूटकर 83,674.92 और 50 शेयरों वाला एनएस निफ्टी 146.65 अंक फिसलकर 25,807.20 पर बंद हुआ। इन दौरान निफ्टी आईटी शेयरों में भारी गिरावट रही और ये 5.51 फीसदी टूटकर बंद हुए। निफ्टी रियल्टी , निफ्टी मीडिया , निफ्टी ऑयल एंड गैस , निफ्टी सर्विसेज), निफ्टी एनर्जी और निफ्टी एफएमसीजी में भी गिरावट रही।

वहीं दूसरी ओर निफ्टी इंडिया डिफेंस , निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में तेजी रही। आज लार्जकैप के साथ ही मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी बड़ी गिरावट रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 283.70 अंक फिसलकर 60,470.85 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 110.90 अंक नीचे आकर 17,344.10 पर बंद हुआ।सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, बीईएल, एसबीआई, टाइटन, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, एलएंडटी, भारती एयरटेल और टाटा स्टील के शेयर लाभ में रहे थे जबकि टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, एमएंडएम, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर गिरे।

इससे पहले आज सुबह बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। आईटी कंपनियों में तेज बिकवाली के चलते बाजार पर दबाव बना रहा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 409 अंकों की गिरावट के साथ 83,825 के स्तर पर पहुंच गयावहीं निफ्टी भी 113 अंक फिसलकर 25,841 पर आ गया।

डॉव जोन्स 0.13 फीसदी गिरा

वहीं आज एशियाई बाजारों में मजबूती रही। जापान का निक्केई 225 पहली बार 58,000 के स्तर को पार कर गया। निक्केई 225 में 0.5 फीसदी की बढ़त रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.9 फीसदी उछला। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी एएसएक्स 200 सूचकांक 0.6 फीसदी बढ़ा। वहीं अमेरिका में बुधवार को प्रमुख सूचकांक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 लगभग स्थिर रहा जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.16 फीसदी फिसला।

सैमसंग पेश करेगा नया गैलेक्सी एस26 एआई स्मार्टफोन

सोल । सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इस महीने अमेरिका में होने वाले गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 इवेंट में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन पेश करेगा। कार्यक्रम 25 फरवरी, को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होगा। कंपनी ने अपने आमंत्रण में कहा- द नेक्स्ट एआई फोन मेक्स योर लाइफ ईजियर। नए स्मार्टफोन, संभवतः गैलेक्सी एस26, में उन्नत एआई फीचर्स होंगे।

यह फोन रोजमर्रा के काम आसान बनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और गैलेक्सी एआई को सहज रूप से एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फोन में नया प्राइवेसी फीचर भी शामिल होगा, जिससे यूजर्स स्क्रीन की जानकारी दूसरों से छिपा सकेंगे। इसके लिए किसी अतिरिक्त स्क्रीन गार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। यूजर्स विभिन्न सेटिंग्स के माध्यम से स्क्रीन की विज़िबिलिटी नियंत्रित कर पाएंगे, जिससे शोल्डर सर्फिंग से बचाव होगा।

सोना-चांदी निवेश में तेजी, बदल रहा है निवेशकों का रुझान: रिपोर्ट

भारतीय निवेशकों के लिए रुपये की कमजोरी अतिरिक्त रिटर्न का अवसर देती है

मुंबई । दुनिया भर में आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सोना और चांदी निवेशकों के लिए फिर से आकर्षक विकल्प बन गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया तेजी केवल अल्पकालिक उछाल नहीं, बल्कि दीर्घकालिक मजबूत ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार बड़े वैश्विक निवेशक अब सोने को अपने पोर्टफोलियो में स्थायी रूप से शामिल कर रहे हैं। पहले इसे केवल संकट के समय सुरक्षित निवेश माना जाता था, लेकिन अब यह लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा बन रहा है। केंद्रीय बैंकों की लगातार सोने की खरीद और ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीदें भी सोने की कीमतों को मजबूत आधार दे रही हैं। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती और डॉलर की कमजोरी विशेष रूप से सोने के लिए सकारात्मक हैं। भारतीय निवेशकों के लिए रुपये की कमजोरी अतिरिक्त रिटर्न का अवसर देती है। चांदी की कीमतों में तेजी सिर्फ निवेश से नहीं बल्कि औद्योगिक मांग से भी प्रभावित है। सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों में बढ़ती खपत चांदी की दीर्घकालिक कीमतों को समर्थन देती है। रिपोर्ट के मुताबिक नए निवेशकों को कुल पोर्टफोलियो का 5-10 फीसदी हिस्सा सोना और चांदी में रखने और निवेश चरणबद्ध करने की सलाह दी गई है। जिन निवेशकों की हिस्सेदारी 25-30 फीसदी से अधिक है, उन्हें पोर्टफोलियो की समीक्षा कर आंशिक मुनाफा वसूलने की सलाह दी गई है।

पतंजलि फूड्स ने 9 महीनों में तोड़ा रिकॉर्ड, राजस्व 29,000 करोड़ के पार

नई दिल्ली,एजेंसी । बाजार की अनिश्चितता और वैश्विक मंदी के बीच बाबा रामदेव की अगुवाई वाली पतंजलि फूड्स ने वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में अभूतपूर्व सफलता दर्ज की। कंपनी का कुल राजस्व 29,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। हालिया तीसरी तिमाही में भी कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा, जिसमें राजस्व 10,500 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 16 फीसदी अधिक है। कंपनी ने तीसरी तिमाही में लगभग 594 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया। हालांकि एबिटा 500 करोड़ रुपये के नीचे दर्ज किया गया, लेकिन कुल ग्रोथ ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। पतंजलि की सफलता के पीछे उसके एफएमसीजी सेगमेंट का अहम योगदान है। इस विभाग ने साल-दर-साल 39 फीसदी की वृद्धि दिखाई और कुल मुनाफे में महत्वपूर्ण हिस्सा रखा। खाद्य तेल का सेक्टर भी कंपनी के लिए रेवेन्यू का बड़ा स्तंभ बना। फूड ऑयल सेगमेंट ने 7,335 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न किया, जिसमें कुल तेल बिक्री का 85 फीसदी ब्रांडेड उत्पादों से हुआ। कंपनी ने न केवल अपने पुराने ग्राहकों को बनाए रखा बल्कि नए बाजारों में भी प्रवेश किया।

सरकार लाएगी देश का पहला मल्टी सेक्टर

नई दिल्ली । सरकार राजमार्ग मुद्रीकरण की सफलता के बाद देश में पहला मल्टी-सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) बनाने पर विचार कर रही है। इसमें सड़क, बिजली, बंदरगाह और जहाजरानी जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियां शामिल होंगी। यह कदम नीति आयोग के नेतृत्व में तैयार राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का हिस्सा है। पहले के इनविट केवल एक ही सेक्टर पर आधारित होते थे, जैसे सड़क या पावर। विशेषज्ञों के अनुसार, मल्टी-सेक्टर इनविट में निवेश का जोखिम कम होगा ।

रिपोर्ट

मार्केट कैप में टीसीएस को पछाड़ कर हासिल किया मुकाम

भारतीय स्टेट बैंक बनी देश की चौथी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी

मुंबई , एजेंसी। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने हाल ही में शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन करते हुए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को पीछे छोड़ दिया है। बुधवार को बाजार बंद होने तक एसबीआई का मार्केट कैप 10.92 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि टीएसीएस का मार्केट कैप 10.52 लाख करोड़ रुपए था। इस वृद्धि के कारण एसबीआई अब देश की चौथी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई है। मार्केट कैप के आधार पर देश की शीर्ष पांच लिस्टेड कंपनियां इस प्रकार हैं- रिलायंस इंडस्ट्रीज 19.87 लाख करोड़, एचडीएफसी बैंक 14.16 लाख करोड़, भारती एयरटेल 11.47 लाख करोड़, एसबीआई 10.92 लाख करोड़ और टीसीएस का मार्केट कैप 10.52 लाख करोड़ रपए था।

एसबीआई के शेयरों में पिछले तीन कारोबारी सत्रों में लगभग 11 फीसदी की तेजी आई। निवेशकों का सरकारी बैंकों में बढ़ता भरोसा और मजबूत तिमाही नतीजे इस तेजी के मुख्य कारण हैं। एसबीआई ने तीसरी तिमाही में *21,030 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो बाजार अनुमानों से करीब 18 फीसदी अधिक है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 9 फीसदी बढ़कर 45,190 करोड़ रुपए हो गई। घरेलू मार्जिन बढ़कर 3.12 फीसदी पर पहुंच गया, जबकि कुल मार्जिन 2.99 फीसदी स्थिर रहा। लोन पोर्टफोलियो में 15.6 फीसदी वृद्धि और जमा में 9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। क्रेडिट कॉस्ट केवल 0.29 फीसदी रही, जो बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। वहीं आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण टीसीएस के शेयरों में पिछले पांच दिनों में लगभग 4 फीसदी की गिरावट आई।

न्यूज इन शॉर्ट

भावान्तर योजना से लाभान्वित किसानों ने कृषि मंत्री कंषाना का किया आभार व्यक्त

भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना का देवास जिले की तहसील कन्नौज के ग्राम ननासा में भावान्तर भुगतान योजना से लाभान्वित किसानों ने स्वागत एवं आभार व्यक्त किया।
कृषि मंत्री कंषाना ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। भावान्तर योजना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिये अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, जिनका सीधा लाभ किसानों तक पहुँच रहा है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

केंद्रीय राज्यमंत्री कुरियन से राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने की भेंट

भोपाल। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन से मुलाकात की। उन्होंने केन्द्रीय राज्यमंत्री कुरियन को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भोपाल में "डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर" की स्थापना का प्रस्ताव भी सौंपा। राज्यमंत्री गौर ने बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित पीएमजेवीके योजना अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास और आधारभूत संरचना को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं में विज्ञान, तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से यह सेंटर स्थापित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। राज्यमंत्री गौर ने बताया कि प्रस्तावित केंद्र के माध्यम से विद्यार्थियों एवं युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, उपग्रह तकनीक और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से परिचित कराया जाएगा। यह केंद्र युवाओं को भविष्य में अंतरिक्ष एवं तकनीकी क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा और विज्ञान शिक्षा को नई दिशा देगा। राज्यमंत्री गौर ने केंद्र सरकार से इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया, ताकि योजना का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में विज्ञान आधारित सशक्त युवा शक्ति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एमपी में राज्य परिवहन प्राधिकार का हुआ पुनर्गठन

भोपाल। एमपी में परिवहन विभाग ने राज्य परिवहन प्राधिकरण का पुनर्गठन कर दिया है। परिवहन विभाग का अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव अब इसका अध्यक्ष नहीं होगा। इसमें अब अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण में सदस्य के रूप में परिवहन आयुक्त होंगे। वहीं प्राधिकरण का सचिव भी मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट उपसचिव या अपर सचिव होगा। परिवहन विभाग के भारसाधक सचिव एवं संयुक्त आयुक्त प्रशासन को प्राधिकरण में सहायता करने हेतु प्राधिकरण विशेष आमंत्रितियों के रूप में आमंत्रित कर सकेगा। इसके पहले परिवहन विभाग ने 28 मार्च 2025 को जब मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत राज्य परिवहन प्राधिकार का गठन किया था तब इसमें अध्यक्ष के रूप में परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को अध्यक्ष बनाया गया था। सदस्य के रूप में परिवहन आयुक्त इसमें शामिल किए गए थे। लेकिन अब पूरे राज्य परिवहन प्राधिकार का पुनर्गठन कर दिया है।

वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन का अभियान

भोपाल। वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण-सत्रों की शुरुआत की गई है। प्रथम चरण में 21 जिला मुख्यालयों पर उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों सहित जिला स्तर पर नामांकित मास्टर ट्रेनर्स के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार के लिए 26 हजार से अधिक ग्रामों को चिह्नित किया गया है। इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पिछले वर्ष से अभियान शुरू किया गया है।

सोशल मीडिया पर डाला पीएम को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट; यूथ कांग्रेस के अज्ञात हैंडलर पर केस

MP में एपस्टीन फाइल से जुड़े मामले में पहली FIR

विजय मत, भोपाल

मध्य प्रदेश में एपस्टीन फाइल विवाद से जुड़े किसी मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। केस जबलपुर नगर निगम के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर शैलेंद्र सिंह कौरव की शिकायत पर अज्ञात शख्स के खिलाफ किया गया है। 9 फरवरी को ओमती थाने में दी गई शिकायत में कहा गया है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से 'ङ्क' पर एआई जनरेटेड तस्वीरें पोस्ट की गई थीं, जिनमें शहर की अलग-अलग जगहों पर कथित यूनिपोल पोस्टर दिखाए गए हैं। इन पोस्टर में एपस्टीन फाइल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एआई से तैयार आपत्तिजनक कंटेंट है। इंजीनियर शैलेंद्र सिंह कौरव का कहना है कि वास्तविकता में ऐसे पोस्टर शहर में लगाए ही नहीं गए थे। इस संबंध में ओमती थाने में 12 फरवरी को FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने धारा 197-ए बीएनएस के तहत यूथ कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सीएसपी रितेश कुमार शिव ने बताया कि जांच के दौरान अब तक दो पोस्ट सामने आई हैं। एक में कार्टून चित्र है जबकि दूसरे में अमेरिका और भारत के प्रधानमंत्रियों की तस्वीर दिखाई गई है। पुलिस ने संबंधित यूनिपोल की जांच की तो पाया गया कि वहां किसी अन्य एजेंसी के वैध पोस्टर लगे हैं। इससे साफ हो गया कि ङ्क पर डाले गए इस कंटेंट से भ्रामक जानकारी फैलाए जाने की आशंका बनी है।

एपस्टीन फाइल केस की पूरी कहानी क्या है: इसकी शुरुआत 2005 में तब हुई, जब फ्लोरिडा में 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि एपस्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को 'मसाज' के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर यह बात अपने माता-पिता को बताई, तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। तब पहली बार जेफ्री एपस्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जांच के दौरान यह सामने आया कि यह अकेला मामला नहीं है। धीरे-धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई, जिन्होंने एपस्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एपस्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। जांच से पता चला कि एपस्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एपस्टीन यहां हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थीं। एपस्टीन अपने निजी जेट 'लोलिता एक्सप्रेस' से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर आता था। वह लड़कियों को पैसों-गहनों का लालच और धमकी देकर मजबूर करता था। इसमें एपस्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। शुरुआती जांच के बाद भी एपस्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई। उसका रसूख इतना था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें वह जेल से बाहर जाकर काम भी कर सकता था। इसमें बताया गया कि वाइंस्टीन ने दशकों तक अभिनेत्रियों, मॉडल्स और कर्मचारियों का यौन शोषण किया। इस घटना ने पूरी दुनिया में सनसनी पैदा कर दी। 80 से ज्यादा महिलाओं ने वाइंस्टीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मी टू (मेरे साथ भी शोषण हुआ) के आरोप लगाए। इसमें एंजेलीना जोली, सलमा हायेक, उमा थरमन और एश्ले जुड जैसे बड़े नाम थे। इसके बाद लाखों महिलाओं ने सोशल मीडिया पर '#MeToo' लिखकर अपने शोषण की कहानियां शेयर कीं।

सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था एपस्टीन

जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी। उस पर 2005 में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। 2008 में उसे नाबालिग से सेक्स की मांग करने का दोषी ठहराया गया। उसे 13 महीने की जेल हुई। 2019 में जेफ्री को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। उसकी जेल में ही मौत हो गई। उसकी पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में उसकी मदद करने के आरोपों में दोषी करार दिया गया। वह 20 साल की सजा काट रही है।

मी टू मूवमेंट की लहर में डूबा एपस्टीन

साल 2009 में जेल से बाहर आने के बाद एपस्टीन लो प्रोफाइल रहने लगा। ठीक 8 साल बाद अमेरिका में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ। साल 2017 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइंस्टीन के खिलाफ कई रिपोर्ट्स छापीं।

---

22 फरवरी को सजेगा हिन्दी लेखिका संघ का वार्षिक अलंकरण समारोह

4 वरिष्ठ साहित्यकारों का विशेष सम्मान, 28 कृतियों को विभिन्न विधाओं में पुरस्कार

विजय मत, भोपाल

हिन्दी लेखिका संघ द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सम्मान एवं कृति पुरस्कार इस वर्ष 22 फरवरी को हिन्दी भवन, श्यामला हिल्स भोपाल में आयोजित भव्य अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे। यह जानकारी संघ की अध्यक्ष डॉ. साधना गंगराडे ने दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष चार वरिष्ठ साहित्यकारों को प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किया जाएगा, वहीं साहित्य की विविध विधाओं में 28 कृतियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वरिष्ठ सम्मान श्रेणी में 'कुसुम कुमारी जैन वरिष्ठता सम्मान' शीला श्रीवास्तव (भोपाल), 'डॉ. फिरोजा मुजफ्फर सेवा सम्मान' डॉ. कुमकुम गुप्ता (भोपाल), 'डॉ. सुशीला कपूर हिंदी सेवी सम्मान' सुमन ओबेरॉय (भोपाल) तथा 'शोभा शर्मा कर्मठता सम्मान' राधारानी चौहान 'मानवी' (भोपाल) को प्रदान किया जाएगा। कृति पुरस्कारों में समग्र साहित्य हेतु डॉ. रंजना शर्मा (भोपाल) को 'प्रभा बरतरिया सारस्वत सम्मान' मिलेगा। उपन्यास के लिए प्रतिमा अखिलेश (जबलपुर), गजल के लिए संगीता चौबे (कुवैत), नाटक के लिए अर्चना मलैया (जबलपुर), लघुकथा हेतु मनोरमा पंत (भोपाल) तथा कहानी विधा में ज्योत्स्ना तिवारी (भोपाल), डॉ. शालिनी बड़ोले (इंदौर) और डॉ. प्रतिभा गुर्जर (भोपाल) को सम्मानित किया जाएगा। गीत विधा में डॉ. प्रतिभा द्विवेदी (भोपाल) और डॉ. मीना भट्ट (जबलपुर), कविता के लिए रेखा कापसे (नर्मदापुरम), कृष्णा राजपूत (जबलपुर) और डॉ. मीना शुक्ला (भोपाल) को पुरस्कार प्रदान होंगे। लोक साहित्य में डॉ. लीला धुलधोये (इंदौर), बाल कविता में डॉ. संगीता पाल (गुजरात), समीक्षा में डॉ. नीलिमा रंजन (भोपाल), यात्रा-वृत्तांत में डॉ. ऋतु जौहरी (जोधपुर) तथा शोध में डॉ. नीलू शुक्ला (भोपाल) को सम्मानित किया जाएगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक सत्येंद्र लोहिया को दी बधाई

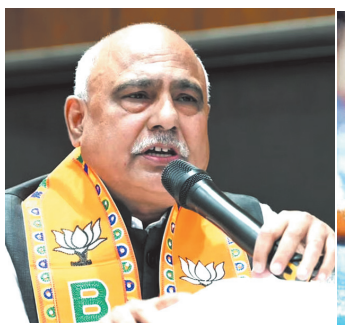

विजय मत, भोपाल

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने पद्मश्री तथा तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित मध्यप्रदेश के गौरव, अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक सत्येंद्र लोहिया को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि सत्येंद्र लोहिया ने विश्व के अत्यंत चुनौतीपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल न्यूज़ीलैंड के कुक स्ट्रेट की लगभग 30 किलोमीटर लंबी समुद्री तैराकी को सफलतापूर्वक पार कर नया इतिहास रचा है। इस असाधारण उपलब्धि के साथ वे कुक स्ट्रेट को पार करने वाले एशिया के प्रथम पैरा तैराक बन गए हैं। यह उपलब्धि साहस, समर्पण और अदम्य इच्छाशक्ति का प्रेरक उदाहरण है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि सत्येंद्र लोहिया की यह सफलता न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। विपरीत परिस्थितियों को चुनौती देते हुए उन्होंने अपने अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उनका संघर्ष और सफलता युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

मप्र में सरकारी जमीन पर बन सकेंगी टाउनशिप

ज्यादा ग्रीन एरिया पर मिलेगा एफएआर का लाभ, डेवलपर्स के लिए 5 करोड़ का टर्नओवर जरूरी

विजय मत, भोपाल

मध्य प्रदेश में अब सरकारी जमीन पर भी बिल्डर टाउनशिप ला सकेंगे। यह कुल टाउनशिप के एरिया के 20 फीसदी या 8 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगी। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम 2026 को जारी कर दिया है। प्रदेश में बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और बेहतर नियोजन के लिए नियम को तैयार किया गया है। बड़े शहरों में टाउनशिप की मंजूरी नगरीय विकास व आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी देगी। नए नियमों के तहत अब बड़ी टाउनशिप के लिए कम से कम 24 मीटर सडक़ जरूरी होगी। इसी तरह किसी भी रेसीडेंशियल प्लॉट के लिए 30 फीट से कम चौड़ी सडक़ नहीं होगी। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में टाउनशिप की मंजूरी साधिकार समिति करेगी। इसमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सचिव अध्यक्ष होंगे। सदस्य के रूप में टीएनसीपी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कमिश्नर, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और संयुक्त संचालक या वरिष्ठ नगर नियोजक इसके सदस्य होंगे। इसमें टाउनशिप के लिए नगर और ग्राम निवेश संचालनालय नोडल एजेंसी होगी। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों में टाउनशिप का अप्रूवल कलेक्टर की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति करेगी। इसमें टीएनसीपी आयुक्त, नगर निगम आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ सदस्य होंगे। वहीं, नगर और ग्राम निवेश के जिला अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसमें टाउनशिप के लिए टीएनसीपी का जिला कार्यालय नोडल एजेंसी होगा।

अब पार्क नहीं घने पेड़ लगाने होंगे: अब टाउनशिप में पार्क के नाम पर ओपन स्पेस से काम नहीं चलेगा। नए नियमों में प्रावधान किया गया है कि पार्क और खुले स्थान के 25 फीसदी हिस्से में घने पेड़ लगाना होंगे। टाउनशिप के अंदर भी सडक़ के किनारे पेड़ लगाने होंगे।

डेवलपर्स के लिए 5 करोड़ का टर्नओवर जरूरी

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम 2026 में डेवलपर्स को लेकर कई नए प्रावधान किए हैं। डेवलपर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए 50 हजार रुपए का पंजीयन शुल्क भुगतान करना होगा, जबकि नवीनीकरण के लिए राशि 25 हजार रुपए रखी गई है।

ग्रीन एरिया से डेढ़ गुना मिलेगा एफएआर

टाउनशिप के अंदर ग्रीन एरिया विकसित करने पर उससे डेढ़ गुना अधिक एफएआर डेवपलपर्स को मिल सकेगा। नए नियमों में प्रावधान किया गया है कि यदि 0।4 हेक्टेयर से कम आकार का अतिरिक्त वानिकी क्षेत्र का प्रावधान किया गया, तो उसे डेढ़ गुना तक टाउनशिप के अंदर एफएआर मिलेगा। इसी तरह डेवलपर्स टाउनशिप में होने वाली बिजली की कुल खपत का 35 फीसदी तक सोलर लाइट से पूरा करता है, तो बिल्डर को अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा। वहीं, यदि बिल्डर टाउनशिप परियोजना का कम से कम 25 फीसदी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट 3 प्राप्त करता है, तो बिल्डर को अतिरिक्त एफएआर की सुविधा दी जाएगी।

मध्यप्रदेश पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

21 करोड़ 97 लाख से अधिक के मादक पदार्थ जब्त

विजय मत, भोपाल

भोपाल, 12 फरवरी 2026। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, तस्करी एवं खेती के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप राजगढ़ एवं नीमच जिले में की गई दो अलग-अलग बड़ी कार्रवाइयों में पुलिस ने 21 करोड़ 97 लाख रूपए से अधिक के मादक पदार्थ (एमडी ड्रग्स एवं अफीम के पौधे) जब्त किए है।

नीमच- 9.76 क्विंटल अवैध अफीम के हरे पौधे जब्त- कीमत लगभग 97 लाख 60 हजार रूपए: जिले की पुलिस चौकी जाट को 11 फरवरी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लुहारिया जाट में कपास की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती की जा रही है। सूचना पर पुलिस द्वारा तकनीकी साधनों एवं ड्रोन सर्चिंग के माध्यम से पुष्टि कर कार्रवाई की गई। पुलिस टीम द्वारा मौके से 11,600 नग हरे पौधे (कुल वजन 09 क्विंटल 76 किलोग्राम) अफीम के पौधे जब्त किए गए।

राजगढ- 21.510 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जप्त, अनुमानित कीमत लगभग 21 करोड रूपए

जिले की राजगढ़ पुलिस दो अलग-अलग कार्यवाही में एमडी ड्रग्स के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना माचलपुर पुलिस ने 11 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर ग्राम माणा के पास से आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपने घर ग्राम अरनिया में एमडी ड्रग्स छिपाकर रखने की जानकारी दी। आरोपी के घर की तलाशी लेने पर पुलिस ने किचन में रखे कार्टून से 10.160 किलोग्राम एमडी ड्रग्स कीमत लगभग 10 करोड़ रूपए जब्त की।

पुलिस अधिकारियों की विधिक दक्षता बढ़ाने हेतु मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भोपाल में दो दिवसीय सेमिनार संपन्न

विजय मत, भोपाल

मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौंरी भोपाल में विगत दिनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा सूचना का अधिकार अधिनियम विषयों पर आयोजित दो दिवसीय सेमिनार का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों की विधिक समझ को सुदृढ़ करना, संवेदनशील प्रकरणों में विधि अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। सेमिनार में मध्यप्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों से आए अधिकारियों को अधिनियमों के नवीनतम संशोधनों और माननीय न्यायालयों द्वारा दी गई कानूनी व्याख्याओं से अवगत कराया गया। साथ ही केस स्टडीज के माध्यम से जटिल प्रकरणों के प्रभावी क्रियान्वयन और विधिक प्रक्रियाओं के व्यावहारिक पक्षों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी के उपनिदेशक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

महाशिवरात्रि पर पशुपतिनाथ मंदिर में भव्य जलाभिषेक 15 को

गंगाजली कलश यात्रा, स्वास्थ्य शिविर और विशाल भंडारे का होगा आयोजन

विजय मत, भोपाल

श्री पशुपतिनाथ मंदिर में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भव्य जलाभिषेक और विविध धार्मिक आयोजन होंगे। पशुपतिनाथ नेपाली समाज द्वारा इस वर्ष 48वां महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। समाज के अध्यक्ष लोकमणी घिमिरे ने बताया कि दोपहर 12 बजे गंगाजली कलश यात्रा से लाए गए पवित्र जल से भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक किया जाएगा। पर्व के तहत 13 फरवरी को गणेश पूजन और 14 फरवरी को गंगाजली कलश पूजन एवं आरती आयोजित होगी। 15 फरवरी की सुबह 8ः30 बजे राम मंदिर, बरखेड़ा से गंगाजली कलश यात्रा प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए मंदिर पहुंचेगी, जहां जलाभिषेक संपन्न होगा।

यात्रा में साधु-संत, विशिष्टजन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 'प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ' अभियान चलाया जाएगा। 15 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक मंदिर परिसर में निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे। समाज ने 16 फरवरी को दोपहर 12 से 4 बजे तक विशाल भंडारे का आयोजन रखा है। आयोजकों ने धर्मप्रेमी नागरिकों से सपरिवार उपस्थित होकर पुण्य लाभ लेने का आग्रह किया है।

जनगणना की तैयारी तेज, आज अफसरों के साथ बनेगी कार्ययोजना

सभी कलेक्टर, संभागायुक्त और निगमायुक्त को दी जाएगी ट्रेनिंग

विजय मत, भोपाल

भोपाल में शुक्रवार को प्रदेशभर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जुटेंगे। एक मई से शुरू होने वाली मकान गणना की तैयारी के तहत राज्य के 55 जिलों के कलेक्टर, 12 संभागायुक्त और 16 नगर निगम आयुक्तों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की उपस्थिति रहेगी, वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इसमें शामिल होंगे। गृह विभाग के सचिव एवं राज्य जनगणना नोडल अधिकारी अभिषेक सिंह ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में उल्लेख है कि जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत 13 फरवरी को प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में मकानों की गणना का कार्य एक मई से शुरू होना प्रस्तावित है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

जनगणना निदेशक का पद खाली

मध्यप्रदेश में जनगणना निदेशक का पद 30 सितंबर 2025 से रिक्त है। उस दिन तत्कालीन निदेशक भावना वालिम्बे सेवानिवृत्त हो गई थीं। इसके बाद से इस पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हो सकी है। फिलहाल यह जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपी गई है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सीता शुक्ला द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप, 11 प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-01, एमपी नगर, भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित एवं ई.एम.एस. 21 इंडस टाउन, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सीता शुक्ला। प्रधान संपादक- विजय शुक्ला
(*समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार)। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र शहडोल होगा। आर.एन.आई. क्रमांक- MPHIN/2015/66998, e-mail vijaymat.sdl@gmail.com। मोबाइल- +91 88899 77997